गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 202
दि. 23.11.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

विदेशी हथियारों से काला हिरण का शिकार: पांचवां आरोपी पकड़ा गया, करोड़ों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी का जाल बेनक़ाब

इं(जीएनएस)। दौर की जांच एजेंसियों के हाथ शनिवार को उस कुख्यात गिरोह की कड़ी का वह हिस्सा लग गया, जिसकी तलाश एक वर्ष से जारी थी। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा शाजापुर के राघौखेड़ी गांव से गिरफ्तार किया गया आजाद सिंह सोलंकी इस बड़े नेटवर्क का पांचवा आरोपी है। इससे पहले मुंबई से दबोचे गए चार तस्करों की निशानदेही पर इस गिरोह की जड़ें लगातार गहराती जा रही थीं, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर की गई यह पहली बड़ी गिरफ्तारी जांच को नए मोड़ पर ले गई है। आजाद सिंह, जिसके पास दो सौ पचास बीघा जमीन है, ने पूछताछ में स्वीकार किया कि शिकार उसके खेतों में ही कराया जाता था। हिरण और चीतल अक्सर उसके क्षेत्र में घूमते थे और इसी प्राकृतिक गतिविधि को वह करोड़ों के अवैध धंधे के लिए इस्तेमाल करता रहा। उसने खुलासा किया कि इम्तियाज और सलमान जैसे बड़े तस्करों ने काला हिरण का शिकार उसके खेतों में ही किया था और यह सब कई बार हुआ, न केवल शाजापुर बल्कि आसपास के इलाकों में भी।

अब तक की जांच में सामने आया है कि गिरोह निर्ममता की हदें पार करते हुए विदेशी असलहों का उपयोग करता था। स्वीडन से तस्करी करके लाई गई लगभग पचास लाख रुपये की हाई-टेक बंदूकें इस अवैध शिकार की रीढ़ थीं। दो हथियार—एक स्वीडिश और दूसरी 12 बोर की भारतीय बंदूक—भोपाल के पास एक एकांत फार्महाउस में मिट्टी खोदकर छिपाए गए थे। हथियारों को छुपाकर रखा गया यह जखीरा दिखाता है कि गिरोह कितना संगठित और तकनीकी रूप से सक्षम था। पूछताछ में यह जानकारी भी सामने आई कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज आमिर ने इन्हें विदेशी गन चलाने की विशेष ट्रेनिंग दी थी, ताकि शिकार बिना आवाज और निशान छोड़े किया जा सके। गिरोह का दायरा केवल मध्य प्रदेश या मुंबई तक सीमित नहीं था। मुख्य आरोपी इम्तियाज की गतिविधियाँ पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका तक फैली थीं। केपटाउन में शिकार करने के उसके पुराने रिकॉर्ड सामने आए हैं और जांच एजेंसियों को विश्वास है कि वह कई देशों में सक्रिय एक बड़े वन्यजीव–तस्करी नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इम्तियाज के मोबाइल से रिकवर किए गए वीडियो और तस्वीरें इस धंधे की क्रूरता को उजागर कर रहे हैं। खाल को प्रोसेस करके विदेश भेजने का काम सलमान करता था, जबकि एयरलाइंस में कार्यरत सबाह खाल की तस्करी के अंतरराष्ट्रीय सौदे फाइनल करती थी। जौहर हुसैन ग्रामीणों से संपर्क करके हिरण और अन्य वन्यजीवों की गतिविधियों का पूरा नक्शा तैयार कर लेता था, ताकि गिरोह बिना जोखिम के शिकार कर सके।

इस पूरी कहानी की शुरुआत पिछले वर्ष 3 दिसंबर 2024 को इंदौर के किशनगंज क्षेत्र में एक लग्जरी कार की सामान्य दिखने वाली चेकिंग से हुई थी। जब कार से 65 किलो काला हिरण का मांस बरामद हुआ, तो पुलिस स्तब्ध रह गई। मौके पर पकड़े गए तीन आरोपी—जौहर, सलमान और इम्तियाज—ने पूछताछ के दौरान वह सिलसिला खोला जिसने राज्य में फैले इस पूरे रैकेट की परतें उधेड़कर रख दीं। इस मामले की गंभीरता देखते हुए स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स को जांच सौंपी गई और धीरे-धीरे यह खुलासा होने लगा कि गिरोह सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व और कान्हा नेशनल पार्क जैसे अत्यधिक संरक्षित क्षेत्रों में भी अवैध शिकार कर चुका है। आजाद सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब इस नेटवर्क के कई और चेहरों के सामने आने की संभावना है। STSF के प्रवक्ता शरद कुमार जाटव का कहना है कि काला हिरण शिकार से जुड़े दो केस पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। मोबाइल डेटा, हथियार बरामदगी, और गिरोह के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शनों को देखते हुए जांच अधिकारी मानते हैं कि अभी और भी बड़े खुलासे होना बाकी हैं। अवैध शिकार और वन्यजीवों की तस्करी का यह संगठित धंधा अब तक जितना दिखाई दे रहा है, उससे कहीं अधिक गहरा और खतरनाक है, और आने वाले दिनों में इसके और भी परतें खुलने की संभावना है।

दिल्ली की साँसें फिर भारी, जहरीली हवा ने तोड़ा हर रिकॉर्ड

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर ज़हर में बदल चुकी है। शनिवार की सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले, तो हवा में घुली धुंध और धुएँ की परत ने साफ़ संदेश दे दिया कि प्रदूषण का कहर लौट आया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज हुआ, जो “गंभीर” श्रेणी की स्थिति है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी हवा का कुछ घंटे तक भी प्रभाव में आना शरीर के लिए भारी नुकसानदायक हो सकता है। सुबह-सुबह पार्कों में टहलने वालों की संख्या अचानक कम दिखी और सड़कों पर भी लोगों के चेहरों पर मास्क की वापसी नज़र आई। यह वही समय है जब कई लोग त्योहारों और शादी-समारोहों की तैयारियों में जुटे होते हैं, लेकिन हवा में मौजूद जहर ने माहौल को डर और चिंता से भर दिया है।

प्रदूषण के तेजी से बढ़ते स्तर को देखते ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने तुरंत बैठक कर आपात कदम उठाने का निर्णय लिया और ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान चरण-3 को पूरी कड़ाई के साथ लागू करने का आदेश जारी किया। आयोग ने यह भी माना कि हालात जिस ढलान पर पहुँच चुके हैं, उसे देखते हुए ग्रैप-4 के शुरुआती उपायों को अभी से अपनाना जरूरी है। यही कारण है कि पहली बार किसी सीजन के बीच में ही सरकार और निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सलाह को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। आयोग ने साफ कहा कि यदि हालात और बिगड़ते हैं तो यह सलाह अनिवार्य भी की जा सकती है।

दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में हवा को सुधारने के लिए मशीनें लगातार चल रही हैं, सड़कों पर पानी का छिड़काव जारी है, लेकिन हवा की गति बेहद धीमी होने और तापमान गिरने के कारण धूल और धुआँ जमीन के पास ही अटका हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा का यह भारीपन कई दिनों तक रह सकता है और बच्चों तथा बुजुर्गों के लिए यह बेहद कठिन समय है। अस्पतालों में पहले से ही सांस फूलने, सीने में जलन, आंखें लाल होने और एलर्जी जैसे मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण जितने लंबे समय तक चलता है, उसके दुष्प्रभाव उतने ही गहरे होते जाते हैं।

स्थिति के लगातार गंभीर होते स्वरूप को देखते हुए आयोग ने राज्यों से अपील की है कि वे निर्माण कार्यों की निगरानी बढ़ाएँ, आवश्यक वाहनों को ही सड़कों पर अनुमति दें और खुले में जलने वाले कचरे पर कड़ी कार्रवाई करें। हालांकि, यह भी असलियत है कि दिल्ली की हवा हर साल इसी मौसम में बिगड़ती है और लाखों लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मजबूर होकर इस जहरीली धुंध को झेलते हैं। सड़क किनारे छोटे दुकानदारों से लेकर रोज कमाने-खाने वाले श्रमिकों तक, सभी के लिए यह मौसम भारी पड़ रहा है।

लोगों के बीच बढ़ती चिंता का माहौल साफ झलक रहा है। कई माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर असमंजस में हैं। कुछ इलाकों में लोग घरों की खिड़कियाँ बंद रखते दिखे, ताकि धुआँ भीतर न घुसे। कई कार्यालय कर्मचारियों को घर से काम करने की तैयारी कर रहे हैं। निजी चिकित्सकों का कहना है कि मास्क पहनना, भाप लेना और घर के भीतर भी एयर-प्यूरीफायर चलाना इस समय सबसे कारगर उपाय है।

हवा के इस भारीपन ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हर साल दिल्ली और एनसीआर को इसी संकट का सामना क्यों करना पड़ता है और आखिर कब ऐसा स्थायी समाधान ढूँढा जाएगा जिससे लोगों की जिंदगी बार-बार इस जहरीले मौसम की गिरफ्त में न आए। फिलहाल, हवा की निगरानी बढ़ाने, लोगों से सतर्क रहने और सरकारी एजेंसियों द्वारा कड़े कदम उठाने की कवायद जारी है, लेकिन अभी यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि दिल्ली को साफ हवा की राहत मिलेगी।

साजिश नाकाम: स्कूल के पास जंगल से मिली 161 जिलेटिन छड़ें, इलाके में अलर्ट - जांच तेज

(जीएनएस)। अल्मोड़ा। शांत पहाड़ी क्षेत्र के विद्यालय और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील खबर ने शुक्रवार को सल्ट थाना क्षेत्र में सन्नाटा तोड़ दिया जब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबरा के पास जंगल में कुल 161 जिलेटिन की छड़ें पाई गईं। स्कूल के कुछ छोटे बच्चों द्वारा संदिग्ध सामग्री दिखाए जाने की सूचना पर इलाके में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देर शाम तक वारदात स्थल की जाँच-पड़ताल कर छड़ें बरामद कर सुरक्षित कब्जे में ले लीं, जबकि बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की उपस्थिति ने घटनास्थल की गंभीरता को और अधिक उभार दिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जिलेटिन की छड़ें सामान्यतः सड़क निर्माण व पत्थर तोड़ने जैसे औद्योगिक उपयोगों में लाई जाती हैं, परन्तु ऐसी विशाल संख्या में ये स्कूल के समीप मिलने पर आशंका जगती है कि इन्हें कहीं और, किसी और उद्देश्य के लिए रखा गया हो सकता है। विशेषज्ञों ने घटनास्थल से सैंपल लेकर फोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिए हैं और फिलहाल किसी विस्फोटक या सक्रिय उपकरण का पता नहीं चला, पर प्रारम्भिक जाँच अभी चल रही है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मिलकर बच्चों व

स्कूल स्टाफ की सुरक्षा के विशेष इंतज़ाम किए और आसपास के क्षेत्रों में पैनी निगरानी बढ़ा दी। घटना की जानकारी मिलते ही थाना सल्ट में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आवश्यक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस की कई टीमें घटनास्थल तथा आस-पास के जंगलों की गहन तलाशी में जुटी हुई हैं। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र सिंह पींचा ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने का आह्वान करते हुए कहा कि जांच बहुत चरम पर और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। उन्होंने बताया कि शुरुआती तौर पर कोई भी निष्कर्ष जल्दबाज़ी में नहीं लिया जा रहा और सच सामने आने पर ही विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

स्थानीय पंचायत और स्कूल प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अभिभावकों को आश्वासन दिया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आवश्यकतानुसार क्लासरूम व आने-जाने के रास्तों की निगरानी बढ़ा दी गई है। अभिभावकों ने मिलकर तत्काल एक बैठक की और कई स्थानीय स्वयंसेवक व शिक्षक बच्चों को मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के साथ ही स्कूल परिसर के आसपास सतत निगरानी पर जोर दे रहे हैं। ग्रामीणों में यह चिंता भी व्याप्त है कि यदि इन जिलेटिन छड़ों का नाम मात्र औद्योगिक उपयोग ही न हो, तो किस मकसद से इन्हें विद्यालय के इतने निकट रखा गया।

जिला प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और वन विभाग तथा राजस्व अधिकारियों से समन्वय कर जंगलों में अतिरिक्त गश्त बढ़ा दी है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण व स्कूल-क्षेत्रों में अचानक ऐसी सामग्री का मिलना कई तरह के संकेत दे सकता है—जैसे कि किसी अवैध निर्माण-सम्बंधी कार्य के लिए संग्रह, किसी तस्करी मार्ग का हिस्सा, या दुर्भाग्यपूर्ण परस्थितियों में असामाजिक तत्वों की किसी साजिश की संभावना। परन्तु इन सभी बातें फिलहाल अनुमान के स्तर पर हैं और पुष्ट प्रमाण मिलने पर ही निष्कर्ष सामने आएंगे।

स्थानीय पुलिस ने आसपास के सभी CCTV फुटेज, वाहन रजिस्ट्री तथा संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल डेटा की भी मांग कर दी है। साथ ही, आस-पास के गांवों और ट्रैक्स पर पूछताछ तेज कर दी गई है। कई ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों से जंगल के मार्गों पर अनजान वाहनों की आवाज और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, पर इन शिकायतों का ब्योरा जुटाना अभी बाकी है। विद्यालय के आसपास के स्कूल बच्चों को भी फिलहाल निर्देश दिए गए हैं कि वे अकेले जंगल की ओर न जाएँ और किसी भी अनजान वस्तु को छूने से परहेज़ करें।

प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और प्रारम्भिक जांच के मद्देनजर, प्रशासन ने कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या सोशल मीडिया पर अटकलें फैलाना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि जांच में बाधा न आए और असली कारण शीघ्रता से पता चल सके। साथ ही पुलिस ने चेताया कि यदि कोई भी व्यक्ति घटना के संबंध में जानकारियों को छुपाता या गलत सूचना देता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अमेरिका के बिना भी जी-20 शिखर सम्मेलन में तैयार हुआ घोषणापत्र जलवायु परिवर्तन बना प्रमुख मुद्दा

(जीएनएस)। जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में जारी जी-20 शिखर सम्मेलन ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। अमेरिका द्वारा पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार करने के बावजूद सम्मेलन में शामिल अन्य सदस्य देशों ने अपने अंतिम घोषणापत्र का मसौदा तैयार कर लिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस प्रक्रिया को “शर्मनाक” करार दिया, लेकिन अन्य देशों ने इसे एक सफल सामूहिक प्रयास के रूप में देखा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा इस सम्मेलन को अफ्रीकी महाद्वीप के लिए कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनका मानना है कि यह सम्मेलन दिखाने का अवसर है कि अफ्रीकी देशों की आवाज़ वैश्विक मंच पर भी निर्णायक हो सकती है। हालांकि, अमेरिका की अनुपस्थिति ने इस लक्ष्य को प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण अवश्य बनाया, क्योंकि आम तौर पर अमेरिकी भागीदारी वैश्विक घोषणापत्रों की अंतिम रूपरेखा पर निर्णायक प्रभाव डालती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी हस्तक्षेप न होने से अन्य सदस्य देशों के बीच कई संवेदनशील मुद्दों—विशेषकर जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशों की आर्थिक सहायता—पर सहज सहमति बन पाई। तैयार किए गए मसौदे में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख एजेंडा के रूप में शामिल किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में इसे “धोखा” करार देते हुए वैश्विक सहयोग का विरोध किया। उन्होंने ब्राजील में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन (COP-30) में कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा और दक्षिण अफ्रीका के एजेंडे को खारिज किया, जिसमें विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु आपदाओं और ऋण संकट से बचाने के उपाय शामिल थे।

इसके बावजूद घोषणापत्र के मसौदे में जलवायु परिवर्तन से जुड़े बिंदुओं को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया। इसमें सदस्य देशों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने, स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने और जलवायु आपदाओं से प्रभावित देशों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने जैसे उपायों पर सहमति जताई है। यह दर्शाता है कि अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद अन्य देशों ने वैश्विक स्तर पर संयुक्त दृष्टिकोण अपनाने और पर्यावरणीय संकट से निपटने की प्रतिबद्धता दिखाई। जी-20 का वैश्विक महत्व भी इस सम्मेलन से स्पष्ट होता है। 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के रूप में स्थापित यह समूह 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद शिखर सम्मेलन का दर्जा प्राप्त कर चुका है। वर्तमान में जी-20 सदस्य देश विश्व GDP का लगभग 85%, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% और वैश्विक आबादी के दो-तिहाई से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में जी-20 शिखर सम्मेलन के निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार नीतियों और पर्यावरण संरक्षण में गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद यह शिखर सम्मेलन एक संदेश देता है कि वैश्विक चुनौतियों—विशेषकर जलवायु संकट—का सामना केवल बड़ी ताकतों पर निर्भर नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और साझा दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है। घोषणापत्र में शामिल बिंदु विकासशील देशों के लिए राहत उपाय और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को प्राथमिकता देते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जी-20 सदस्य देशों ने वैश्विक जिम्मेदारी के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता दिखाई है।

महारेरा का सख्त कदम: मुआवज़ा वसूली को प्रभावी बनाने के लिए नई प्रक्रिया लागू, लापरवाह डेवलपर्स को अब जेल तक भेजा जा सकेगा

(जीएनएस)। मुंबई। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महारेरा) ने घर खरीदारों को समय पर न्याय दिलाने और लापरवाह डेवलपर्स पर शिकंजा कसने के लिए एक नया और बेहद कठोर ढांचा लागू कर दिया है। हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद तैयार की गई यह नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) न केवल मुआवज़ा वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि उन डेवलपर्स पर भी सीधी कार्रवाई का रास्ता खोलेगी जो आदेशों का पालन करने में लापरवाही बरतते रहे हैं। यह पहली बार है जब मुआवज़ा न चुकाने वाले बिल्डरों के मामलों को सीधे प्रिंसिपल सिविल मजिस्ट्रेट तक भेजे जाने की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे उन्हें तीन साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। रेरा में शिकायतें अक्सर पज़ेशन में देरी, निर्माण की खराब गुणवत्ता, वादा किए गए पार्किंग स्पेस की अनुपलब्धता और भवन मानकों के उल्लंघन जैसे मामलों से जुड़ी होती हैं। पहले प्रक्रिया लंबी और जटिल होने के कारण घर खरीदारों को वर्षों तक राहत नहीं मिल पाती थी। नई एसओपी के साथ स्थिति बदलने जा रही है। अब महारेरा का लक्ष्य है कि आदेश की तारीख से 60 दिनों के भीतर मुआवज़ा या राहत संबंधी निर्णय जारी कर दिए जाएं, ताकि शिकायतकर्ता को समयबद्ध न्याय मिल सके।

यदि किसी डेवलपर पर मुआवज़ा देने का आदेश जारी कर दिया जाता है और फिर भी वह अपने दायित्व का पालन नहीं करता, तो खरीदार को महारेरा में अनुपालन शिकायत दर्ज करनी होगी। चार सप्ताह के भीतर इस शिकायत पर सुनवाई होगी और डेवलपर को आदेश पूरा करने के लिए एक अंतिम मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी पालन न करने पर दबाव बढ़ाने के लिए डेवलपर को एफिडेविट के जरिए अपनी सभी चल-अचल संपत्तियों, निवेशों और बैंक खातों का विवरण प्रस्तुत करना होगा—जिसे आगे की कार्रवाई की आधारशीला माना जाएगा। प्रक्रिया का सबसे निर्णायक चरण इसके बाद शुरू होता है। महारेरा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संबंधित जिले के कलेक्टर को वारंट भेजेगा, जिसके तहत बैंक खातों से राशि जब्त करने, संपत्तियों को सीज़ करने या अन्य वित्तीय दंडात्मक कदम उठाने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर की यह कार्रवाई सीधे-सीधे वसूली को तेज करेगी, जिससे खरीदार को वास्तविक मुआवज़ा मिलने का रास्ता साफ होगा।

अगर इन सभी चरणों के बावजूद डेवलपर भुगतान नहीं कर पाता या जानबूझकर टालमटोल करता है, तो मामला सीधा फर्स्ट क्लास सिविल मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाएगा। यहां इंडियन ज्यूडिशियल कोड के तहत आरोपी डेवलपर को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यह प्रावधान रियल एस्टेट क्षेत्र में पहली बार इतने व्यापक रूप में लागू किया जा रहा है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार और न्यायिक प्रणाली घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए अब और सख्त रवैया अपनाने के लिए तैयार हैं। नई एसओपी का उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि रियल एस्टेट सेक्टर की विश्वसनीयता वापस स्थापित हो और घर खरीदने वाले आम लोगों का भरोसा फिर मजबूत हो। वर्षों से पेंडिंग पड़े मामलों और अधूरे प्रोजेक्ट्स से परेशान खरीदारों के लिए यह कदम एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। महारेरा उम्मीद कर रहा है कि कठोर कानूनों के चलते डेवलपर्स आदेशों के अनुपालन को प्राथमिकता देंगे और विवादों का समाधान जल्दी होगा, जिससे रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता और अनुशासन लौट सके।

संपादकीय

त्रासदी की जवाबदेही

यह खबर विचलित करने वाली है कि दिल्ली में एक सोलह वर्षीय छात्र और जयपुर में एक नौ साल की छात्रा ने स्कूल की असहज स्थितियों के चलते आत्महत्या कर ली है। निस्संदेह, ये आत्महत्या की घटनाएं एक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करती हैं। भारत के स्कूल, जिनका उद्देश्य बच्चों का पालन-पोषण और सुरक्षा करना है, तेज़ी से ऐसे स्थानों में बदल रहे हैं जहां क्रूरता, उपेक्षा और अनियंत्रित अधिकार बच्चों के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ये त्रासदियां कोई असामान्य बात नहीं हैं; ये एक असफल व्यवस्था के लक्षण हैं। तीसरी भयावह घटना महाराष्ट्र के वसई की है जहां एक तेरह साल की छात्रा को किसी कारणवश स्कूल देर से पहुंचने पर शिक्षक ने अमानवीय सजा दी। छात्रा को स्कूल बैग के साथ सौ उठक-बैठक लगाने को बाध्य किया गया। यह तथ्य नजरअंदाज करते हुए कि वह एनीमिया से पीड़ित है। छात्रा कुछ देर के बाद बेहोश हो गई और कालांतर में उसकी मौत हो गई। निस्संदेह, एक छात्र व एक छात्रा की आत्महत्या और महाराष्ट्र के वसई में छात्रा की उठक-बैठक लगाने से हुई मौत एक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करती है। स्कूल जिनका उद्देश्य छात्र-छात्राओं को पालन-पोषण और सुरक्षा करना था, वे बच्चों के जीवन पर संकट की वजह बन रहे हैं। वहां शिक्षकों की संवेदनहीनता, उपेक्षा और सख्त व्यवहार कई बच्चों का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। ये त्रासदियां असामान्य बात नहीं, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की असफलता की कहानी कहती है। दिल्ली में, मेट्रो स्टेशन से छलांग लगाने वाले किशोर ने अपने शिक्षकों के हाथों अपमान का हृदय विदारक वर्णन करते हुए एक पत्र छोड़ा है। उसके माता-पिता ने छात्र के उत्पीड़न का आरोप शिक्षकों पर लगाया है। उनका आरोप है कि उसे छोटी-छोटी बात पर डांटा गया, निष्कासन की धमकी दी गई और सहपाठियों के सामने मजाक उड़ाया गया।

आत्महत्या करने वाले छात्र के अभिभावकों द्वारा प्राथमिकी में बताया गया कि छात्र ने मन में आने वाले आत्महत्या के विचार से काउंसलर को अवगत कराया था। लेकिन शिक्षकों ने न तो माता-पिता को सूचित किया और न ही उसे इस दिशा में सोचने से रोकने के लिये कोई सलाह दी गई। निश्चित रूप से जब कोई छात्र अपनी किसी गंभीर समस्या का जिक्र करता है तो ऐसे में उदासीनता हिंसा का एक रूप ही कही जाएगी। वहीं दूसरी ओर जयपुर में नौ वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में सीबीएसई की जांच में संस्थागत उदासीनता का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि पिछले 18 महीने से छात्रा अन्य छात्राओं द्वारा परेशान की जा रही थी। जिस दिन छात्रा ने आत्महत्या की, उस दिन वह अपनी सहपाठियों द्वारा लिखी गई, अश्लील सामग्री से स्पष्ट रूप से व्यथित होकर 45 मिनट में पांच बार अपनी शिक्षिका के पास शिकायत लेकर गई थी। शिक्षिका ने उसकी दलीलों को खारिज कर दिया और उलटा उसे ही डांटा। निश्चित रूप से शिक्षिका ने छात्रा की देखभाल के अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया। कमोबेश वसई की घटना भी शिक्षक की घोर संवेदनहीनता को ही दर्शाती है, जिसने एनीमिया से पीड़ित छात्रा से बैग के साथ सौ उठक-बैठक लगवाई। हालांकि, शिक्षक को गैर-इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन छात्रा का जीवन वापस नहीं लौटाया जा सकता। निश्चित रूप से तीन राज्यों में तीन विद्यार्थियों की मौत हमारी संवेदनहीन व्यवस्था को ही दर्शाती है। दरअसल, आज स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिये कारगर कानून के अलावा भावनात्मक संकट की रिपोर्टिंग अनिवार्य करने की जरूरत है। स्कूलों में प्रशिक्षित परामर्शदाता होने चाहिए। साथ ही किसी बच्चे के भावनात्मक व शारीरिक शोषण रोकने के लिये सख्त दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ताकि भविष्य में किसी संभावना का यूं दुखद अंत न हो। इक्कीसवीं सदी के बच्चे नये दौर में नये सपनों की उड़ान लिए हुए हैं, वे अपनी अस्मिता व सम्मान के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। एकाकी परिवार में वे मां-बाप के लाड-प्यार से पलते हैं। जब भी उनके अहम को ठेस लगती है वे असहज हो जाते हैं। ऐसे में शिक्षकों का सतर्क व संवेदनशील व्यवहार जरूरी है।

गले में स्टेथोस्कोप, मन में जहर, खतरनाक है आतंकवाद का बदलता रूप

“ डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन, ये तीनों उस गिरोह के केंद्र में थे, जो देश की राजधानी में बड़े पैमाने पर जनसंहार की योजना बना रहा था। इन सभी की प्रोफैशनल पहचान ने इतना मजबूत आवरण तैयार कर दिया था कि कोई इन्हें शक की निगाह से देख ही नहीं सकता था।

भारत को अब जिस नए तरह के आतंक का सामना करना पड़ रहा है, वह सीमा-पार से नहीं बल्कि क्लासरूम, लैब और अस्पतालों के भीतर से जन्म ले रहा है। आतंकवाद का रूप अब बदल चुका है। वह अब सीमापार की घुसपैठ, जंगलों में छिपे गिरोहों या हथियारबंद टुकड़ियों तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी जड़ें उन सफेदपोश और शिक्षित लोगों तक पहुंच चुकी हैं, जिन्हें समाज सम्मान की दृष्टि से देखता था। आतंक का नया चेहरा वह है, जो लैब कोट पहनता है, रिसर्च पेपर लिखता है, अस्पताल में ड्यूटी करता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है और आईटी कंपनियों में काम करता है। यही है ‘व्हाइट कॉलर टेरर’, जो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चुनौती बन गया है। ‘व्हाइट कॉलर टेरर’ यानी शिक्षित, तकनीकी दक्ष और समाज में सम्मानित वे लोग, जो कट्टरपंथ की डिजिटल फैक्ट्रियों में वाहक बनते जा रहे हैं। दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोट और डॉक्टरों के बड़े मॉड्यूल का पकड़ा जाना इस नई साजिश का सबसे भयानक संकेत है। ये न आतंकी दिखते हैं, न किसी पर संदेह होता है। लाल किले के पास कार में हुए विस्फोट में 11 लोग मारे गए और कई घायल हुए। विस्फोटक कार के चालक की पहचान जब सामने आई तो देश स्तब्ध रह गया क्योंकि वह कोई अपराधी, कोई पुराना संदिग्ध या किसी गिरोह का सदस्य नहीं बल्कि डॉक्टर था। पुलवामा का रहने वाला युवक उमर मोहम्मद उन तीन डॉक्टरों का साथी निकला, जिनके पास से फरीदाबाद में लगभग 3000 किलो विस्फोटक और हथियार बरामद हुए थे। यह कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि एक बेहद गहरी और सुनियोजित आतंकवादी साजिश की परतें खोलने वाला तथ्य है।

डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन, ये तीनों उस गिरोह के केंद्र में थे, जो देश की राजधानी में बड़े पैमाने पर जनसंहार की योजना बना रहा था। इन सभी की प्रोफैशनल पहचान ने इतना मजबूत आवरण तैयार कर दिया था कि कोई इन्हें शक की निगाह से देख ही नहीं सकता था। इसी मॉडल का चौथा सदस्य डॉक्टर मोहिउद्दीन गुजरात पुलिस के आतंकवाद-निरोधक दस्ते की गिरफ्त में आया। चीन से मेडिसिन की पढ़ाई कर लौटे इस युवक को राइसिन जैसा घातक जहर तैयार करते हुए पकड़ा गया, जो एक ही बार में सैंकड़ों लोगों की जान ले सकता था। यह घटनाएं पहली नहीं हैं लेकिन निश्चित रूप से सबसे खतरनाक हैं। पुणे का डॉक्टर अदनान अली सरकार हो या बेंगलुरु की बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियर अथवा आईटी प्रोफैशनल्स, पिछले एक दशक में कई उच्च शिक्षित लोग आतंकी संगठनों के लिए काम करते हुए पकड़े जा चुके हैं। ऑनलाइन पहचान छिपाने के लिए फर्जी नाम, छद्म प्रोफाइल, एन्क्रिप्टेड चैट और डार्क वेब समूहों का इस्तेमाल अब इनका सामान्य हथियार बन चुका है। आइएस, अल-कायदा या छोटे स्थानीय मॉड्यूल, ये सभी इस नए वर्ग को अपनी ‘बौद्धिक सेना’ बनाने में सक्रिय हो चुके हैं।

यह धारणा अब पूरी तरह मिथ्या साबित हो चुकी है कि केवल गरीब, वंचित या अशिक्षित लोग ही मजहबी उन्माद या सामाजिक उत्पीड़न के कारण कट्टरपंथी बनते हैं। हाल के वर्षों में आतंक के रास्ते पर चलने वाले लोगों की सूची देखें तो स्पष्ट होता है कि उनमें बड़ी संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ और डिग्रीधारी युवा शामिल हैं। उनकी समस्या न तो आर्थिक है, न सामाजिक बल्कि वैचारिक है। वे इंटरनेट पर उपलब्ध कट्टरपंथी सामग्री, डार्क वेब चैट रूम, टेलीग्राम चैनलों और गहरे धार्मिक उन्माद से प्रेरित वीडियो के माध्यम से धीरे-धीरे विचलित होते हैं और फिर एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं, जिसे वे खुद भी कभी समझ नहीं पाते। भारत में केरल, कश्मीर, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, जहां प्रोफैशनल डिग्री वाले व्यक्ति आइएस, जैश, लश्कर या अल-कायदा के लिए काम करते हुए पकड़े गए। कुछ ने तो खुद के ‘जिहादी मॉड्यूल’ भी बना लिए, जिनके नाम मजहबी संदर्भों से प्रेरित थे, जैसे गजवा-ए-हिंद के नाम पर सक्रिय कई छोटे समूह। ये संगठन मजहबी मान्यताओं की मनचाही व्याख्याएं करके, उसे ‘धर्मयुद्ध’ का रूप देकर अत्याचार, जनसंहार और हिंसा को जायज ठहराते हैं। समय-समय पर इन पर फतवे भी जारी हुए, लेकिन कट्टरपंथियों पर उनका कोई असर नहीं पड़ा।

जिहादी आतंक कोई आत्मस्फूर्त हिंसा नहीं बल्कि एक घिनौनी विचारधारा का परिणाम है। यह विचारधारा मजहबी ग्रंथों की विकृत व्याख्याओं पर आधारित है। अब जब डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक भी इस विचारधारा का शिकार होने लगें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या कहीं गहरे छिपी है। सरकार, पुलिस और एजेंसियां अकेले इस विचारधारात्मक युद्ध को नहीं जीत सकती, यह समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। परिवारों, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक समूहों और सामाजिक नेतृत्व को मिलकर यह समझना होगा कि कट्टरपंथ कैसे जन्म लेता है और कैसे फैलता है। व्हाइट कॉलर टेरर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह संदेह के दायरे से बाहर रहता है। समाज में सम्मानित होने के कारण डॉक्टर, इंजीनियर या आईटी विशेषज्ञ कोई हथियार लेकर नहीं घूमते। वे किसी सूची में नहीं होते। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। वे तकनीक, बैंकिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, एन्क्रिप्शन और साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ होते हैं। यही कारण है कि वे निगरानी तंत्र को चकमा देने में सफल हो जाते हैं। वे वीपीएन, क्रिप्टो ट्रांजैक्शन, डार्क वेब चैट, प्रोटॉन मेल और ऑटो-डिलीट चैट का इस्तेमाल करते हैं। वे विस्फोटकों की खरीद-फरोख्त के लिए फर्जी पहचान बनाते हैं। उनके खाते, उनके लेन-देन और उनकी यात्राएं सामान्य नागरिक जैसे दिखते हैं। यही कारण है कि एजेंसियों के लिए इनके व्यवहार का पैटर्न पहचानना ही सबसे कठिन चुनौती बन जाता है।

आज आतंकवादी संगठनों की रणनीति बदल चुकी है। वे अब जंगलों या सीमाओं पर नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, लैब्स और तकनीकी संस्थानों में नए सदस्य खोजते हैं। टेलीग्राम और सिग्नल पर ‘भाईजान’, ‘शहीद’, ‘मुजाहिद’, ‘काफिरों के खिलाफ जंग’ जैसे भावनात्मक शब्दों में संदेश भेजे जाते हैं। ऐसे संदेश धार्मिक, सामाजिक या न्याय के नाम पर ‘कथित अन्याय’ का चित्र बनाते हैं और युवा धीरे-धीरे कट्टरपंथी बन जाते हैं। यह ‘ब्रेन वॉशिंग’ चुपचाप होती है, किसी को पता तक नहीं चलता। डॉक्टर और इंजीनियर आखिर आतंकी क्यों बन रहे हैं और आतंकवादी कौनसे नैरेटिव से प्रेरित हैं, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। हर जिहादी संगठन अपने हिंसक कृत्यों को मजहबी मान्यताओं की आड़ में सही ठहराता है। यही कारण है कि आतंक के खिलाफ होने वाले फतवों का कोई असर नहीं होता क्योंकि समस्या धार्मिक आस्थाओं की राजनीतिक और हिंसक व्याख्याओं में है। व्हाइट कॉलर आतंकी सबसे खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि उन्हें रोकना सबसे मुश्किल है। इन पर समाज भरोसा करता है और ये विश्वास को ही हथियार बनाकर आतंक फैलाते हैं। यही कारण है कि अब भारत को सुरक्षा का एक ऐसा नया फ्रेमवर्क तैयार करना होगा, जो केवल निगरानी पर आधारित न हो बल्कि रैडिकलाइजेशन को रोकने के लिए शिक्षा, समाज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में व्यापक सुधार भी करे।

बहरहाल, एजेंसियों को अब व्यवहार आधारित एआई निगरानी, डिजिटल फुटप्रिंट विश्लेषण, क्रिप्टो-ट्रैकिंग और इंटरनेशनल डेटा-शेयरिंग की दिशा में और मजबूत कदम उठाने होंगे। शिक्षण संस्थानों में साइबर-रेडिकलाइजेशन पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे। धार्मिक नेतृत्व को कट्टरपंथी व्याख्याओं के खिलाफ स्पष्ट और ठोस संदेश देने होंगे। लाल किले का धमाका और उससे जुड़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल स्पष्ट चेतावनी है कि अगली लड़ाई जंगलों या सीमा पर नहीं होगी बल्कि क्लासरूम, लैब, अस्पताल, ऑफिस और वर्चुअल दुनिया में लड़ी जाएगी। यदि हमने इस खतरे को अभी नहीं समझा तो आतंक का यह नया चेहरा उतना ही विनाशकारी होगा, जितना हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसे में भारत की सुरक्षा केवल हथियारों पर नहीं बल्कि समाज के नैतिक ढ़ांचे, शिक्षण संस्थानों की जागरूकता और नागरिकों की सतर्कता पर निर्भर है।

प्रेरणा

जीवन की दीप-ज्वाला और सिद्धार्थ का महाबोध

राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी केवल अतीत का प्रसंग नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की मौन पुकार है जो जीवन के अर्थ को खोजता है। यह यात्रा संघर्ष से शुरू होती है, संदेहों से गुजरती है, और अंत में उस रोशनी तक पहुँचती है जो न मिटती है, न बदलती है। यह कहानी उस रोशनी की है—जिसने एक राजकुमार को बुद्ध बनाया, और एक साधारण जीवन को अनंत करुणा से भर दिया।

सिद्धार्थ के जन्म के साथ ही ज्योतिषियों ने बता दिया था कि यह बालक साधारण नहीं है; इसमें या तो चक्रवर्ती सम्राट बनने की क्षमता है या फिर महान संत बनने की। पिता को भय था कि पुत्र वैराग्य की ओर न मुड़ जाए, इसलिए उनके लिए एक ऐसा संसार रचा गया जिसमें न दुःख का स्पर्श हो, न बुढ़ापे का परिचय, न रोग की छाया। परंतु मन की आँधियाँ महलों की दीवारों को नहीं पहचानतीं। एक दिन, जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण को निकले, उन्हें वह सच्चाई दिखी जिसे अब तक उनसे छिपाया गया था—एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगग्रस्त मनुष्य, एक मृत शरीर और एक संन्यासी के शांत चेहरे की झलक। इन चार दृश्यों ने उनकी आत्मा में वह तूफान भर दिया जिसने आगे चलकर दुनिया की दिशा बदल दी।

रात भर वे करवटें बदलते रहे। महलों की रौशनी अब उन्हें धुंधली लगने लगी थी। मन में प्रश्न उठ रहा था—यदि यह संसार क्षणिक है, यदि सुख और वैभव समय के साथ मिट जाते हैं, तो क्या मनुष्य के भीतर छिपा कोई ऐसा सत्य नहीं है जो अविनाशी हो? इसी प्रश्न ने महलों के द्वार छोड़कर जंगलों के द्वार खोल दिए। उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए और साधारण सन्यासी की तरह भिक्षा-पात्र लेकर सत्य की खोज में निकल पड़े।

कुछ वर्षों तक सिद्धार्थ कठोर साधना में लगे रहे। वे दिन में केवल एक दाना खाते, कभी-कभी वह भी नहीं। शरीर हड्डियों का ढाँचा बन चुका था, त्वचा काले निर्विकार पत्थर जैसी दिखती थी। परंतु मन के भीतर का अंधकार अब भी छँटा नहीं था। उन्होंने अध्यात्म के अनेक रूपों को आजमाया, कई गुरुओं की शिक्षाएँ सुनीं, पर सत्य की वह झलक अब भी उनकी पकड़ से दूर थी। उनके साथी तपस्वी मानते थे कि शरीर को नष्ट कर देने से आत्मा मुक्त हो जाती है। सिद्धार्थ भी इस भ्रम में कई वर्षों तक जीते रहे, परंतु मन कहीं भीतर से सवाल पूछता था—क्या सत्य केवल कष्ट में ही छिपा है?

यही वह समय था जब सुजाता नाम की एक साधारण ग्रामबाला प्रतिदिन उन्हें खीर लाकर देती थी। उसके मन में यह विश्वास था कि यह तपस्वी कोई देवता है, और उसे भोजन अर्पित करना पुण्य है। सिद्धार्थ महीनों तक मौन, निर्लिप्त बैठे रहते। उनके भीतर एक अदृश्य संघर्ष चलता रहता—क्या तपस्या इतनी कठोर होनी चाहिए कि शरीर ही टूट जाए? क्या अतिशय त्याग भी एक प्रकार का अहंकार नहीं बन जाता?

एक पूर्णिमा को, जब आसमान श्वेत-रजत प्रकाश से भरा था, पास से गुजरती कुछ बालिकाएँ वीणा-गीत गा रही थीं। गीत की पंक्तियाँ सरल थीं, पर उनके भीतर जीवन का गहरा सार छिपा था—“वीणा के तार को इतना मत कसो कि वह टूट जाए, और इतना भी मत ढीला छोड़ो कि वह स्वर ही न दे सके।” सिद्धार्थ के भीतर यह पंक्ति किसी बिजली की तरह कौंधी। अचानक उन्हें लगा जैसे यह संदेश सीधे उनके मन के लिए था। वर्षों की तप, अधीर खोज और कठोर त्याग—सब एक ही क्षण में सारहीन प्रतीत होने लगे। उनके भीतर एक नई समझ जन्मी—जीवन का सत्य न बाँध में है, न त्याग में; न कठोरता में है, न विलासिता में; जीवन का सत्य मध्यम मार्ग में है—उस संतुलन में, जहाँ मन और शरीर साथ चलें, विरोध में नहीं।

उन्होंने उसी क्षण मन ही मन निर्णय लिया कि अब वे शरीर को कष्ट नहीं देंगे। उन्होंने सुजाता की खीर ग्रहण की और वर्षों के बाद पहली बार अपने भीतर जीवन की गर्माहट महसूस की। मानो शरीर में नहीं, आत्मा में भोजन उतर गया हो। उनके विचार निर्मल होने लगे, ध्यान गहरा होने लगा, और मन ऐसा शांत हो गया जैसे कोई नदी उफान छोड़कर समुद्र में विलीन हो गई हो। उसके बाद सिद्धार्थ ने पूर्ण जागरण की साधना शुरू की। वे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, यह संकल्प लेकर कि जब तक सत्य का अंतिम द्वार नहीं खुलता, वे वहाँ से नहीं उठेंगे। रात बीतने लगी। पहला पहर छाया और स्मृतियों की परतें खोल गया। दूसरा पहर जन्मों के कर्मों का गुह्य ज्ञान प्रकट करने लगा। तीसरे पहर में संसार की गति, जन्म, मरण और पुनर्जन्म का रहस्य सामने आया। और जब भोर की पहली किरण ने आकाश को हल्का किया, सिद्धार्थ के भीतर संसार का वह सबसे बड़ा प्रकाश फूट चुका था—सम्यक् बोध।

उसी क्षण एक मनुष्य बुद्ध बना—वह जिसने जन्म और मृत्यु से ऊपर उठकर संसार के दुःख का अर्थ समझ लिया। उनके भीतर अज्ञान की रात समाप्त हो चुकी थी, और करुणा का सूर्य उदित हुआ था। अब वे जानते थे कि जीवन का मार्ग वही है जिसमें न अति है, न न्यूनता; न कसाव है, न ढीलापन। मध्यम मार्ग ही वह सेतु है जो मनुष्य को दुःख से मुक्ति की ओर ले जाता है।

सिद्धार्थ की यह यात्रा हजारों वर्षों बाद भी मानवता को राह दिखाती है। यह बताती है कि जीवन की दीप-ज्वाला तभी प्रज्वलित होती है जब मनुष्य संतुलन, करुणा और सम्यक् दृष्टि से दुनिया को देखना सीखता है। यही बोध, यही जागरण, यही मध्यम मार्ग—सच्ची स्वतंत्रता का द्वार है।

नागरिक कर्तव्यों के अनुपालन से आर्थिक विकास को दी जा सकती है गति

वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों पर करों का बोझ कम करने का ईमानदार प्रयास किया है। सबसे पहिले आयकर की सीमा को 12 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया (जिसका मतलब है कि 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले नागरिकों को अब आयकर नहीं देना होगा), इसके बाद वस्तु एवं सेवा कर की दरों का युक्तिकरण करते हुए पूर्व में लागू चार दरों (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत) को केवल दो दरों (5 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत) में परिवर्तित कर दिया गया। इससे भारत में 90 प्रतिशत से अधिक उत्पाद एवं सेवाओं पर करों की दर में भारी कमी दृष्टिगोचर हुई है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की दरों में की गई उक्त कमी के चलते नागरिकों के हाथो में खर्च करने हेतु अधिक राशि की बचत हुई है और इसका प्रभाव इस वर्ष दीपावली एवं अन्य त्यौहारों के शुभ अवसर पर उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री में हुई भारी भरकम वृद्धि के रूप में देखने को मिला है। वर्ष 2025 के दीपावली एवं अन्य त्यौहारों के समय 5.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि के उत्पाद एवं 65,000 करोड़ रुपए की राशि की सेवाओं की बिक्री हुई है, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती की है। वर्ष 2025 में रेपो दर को 6.50 प्रतिशत से घटाकर 5.50 प्रतिशत तक नीचे लाया गया है, इससे भारत में नागरिकों एवं उद्योग जगत को सस्ती दरों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध हो रही है। दिसम्बर 2025 में भी रेपो दर में 25 आधार बिंदुओं की कमी किये जाने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इससे ऋणों पर ब्याज दर में और अधिक कमी हो सकती है। साथ ही, अब तो केंद्र सरकार एवं कई राज्य सरकारों द्वारा भी किसानों, बुजुर्गों एवं महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ही सहायता राशि जमा की जा रही है, जिससे भारतीय नागरिकों के हाथों में अधिक मुद्रा उपलब्ध हो रही है और वे अधिक मात्रा में बाजार से उत्पादों को खरीदने में सक्षम हो रहे हैं। भारत में, हाल ही के समय में, आम जनता की क्रय शक्ति इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि मुद्रा स्फीति की दर पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सका है और खुदरा महंगाई की दर 2 प्रतिशत से भी नीचे आ गई है, जो 10/12 वर्ष पूर्व तक 10 प्रतिशत के आसपास रहती थी। कुल मिलाकर, अब यह कहा जा सकता है कि भारत 10 प्रतिशत वार्षिक विकास दर को हासिल करने की ओर तेजी से अपने कदम बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 65 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे भारत में अति गरीब नागरिकों की संख्या तेजी से कम हो रही है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले करोड़ों नागरिकों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सका है। भारत में लगातार कम हो रही अति गरीब नागरिकों की संख्या की प्रशंसा वैश्विक वित्तीय संस्थानों, विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि, द्वारा भी समय समय पर की गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय नागरिकों को करों में उक्त वर्णित रियायतें देनें एवं गरीब वर्ग को मुफ्त अन्न उपलब्ध कराने एवं उनके खातों में सीधे सहायता राशि जमा कराने जैसी योजनाओं को चलाने के बावजूद केंद्र सरकार के बजटीय घाटे को लगातार कम करने में सफलता मिल रही है। केंद्र सरकार का बजटीय घाटा कोविड महामारी के खंडकाल में लगभग 10 प्रतिशत तक पहुंच गया था जो प्रतिवर्ष लगातार कम होते होते वर्ष 2026 में 4.4 प्रतिशत के स्तर पर नीचे आने का अनुमान लगाया गया है। यह सम्भव हो सका है क्योंकि भारत के नागरिकों द्वारा अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर की राशि को ईमानदारी से सरकार के खजाने में जमा कराया जा रहा है। भारत में हाल ही के वर्षों में कर अनुपालन में काफी सुधार दिखाई दिया है।

यह सही है कि किसी भी देश में आर्थिक विकास की दर को तेज करने में, उस देश में, इस संदर्भ लागू की जाने वाली आर्थिक नीतियों का प्रभाव पड़ता है परंतु यदि उस देश में समाज भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करे तो आर्थिक विकास की गति को और अधिक तेज किया जा सकता है। अर्थात, समाज को अपने नागरिक कर्तव्यों पर आज और अधिक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष में संघ के स्वयंसेवकों द्वारा पंच परिवर्तन नामक कार्यक्रम को समाज के बीच ले जाने का प्रयास बड़े उत्साह से किया जा रहा है। पंच परिवर्तन कार्यक्रम में 5 बिंदु शामिल हैं - नागरिक कर्तव्य, कुटुम्ब प्रबोधन, पर्यावरण, समरसता एवं स्व के भाव का जागरण (इसमें स्वदेशी अर्थात देश में निर्मित उत्पादों का उपयोग भी शामिल है)। इन 5 आयामों के माध्यम से समाज परिवर्तन के कार्य को गति देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें भारतीय नागरिकों को अपने नागरिक कर्तव्यों के अनुपालन पर भी विशेष ध्यान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। देश के कानूनों का पालन करना और उनका सम्मान करना नागरिकों की जिम्मेदारी है। इस कर्तव्य को पूरा करने से समुदाय में अनुशासन और सुरक्षा की भावना पैदा होती है। दैनिक जीवन के छोटे छोटे नियमों का पालन करने से सामाजिक अनुशासन का विकास होता है। जैसे, यातायात नियमों का पालन करना। जहां आवश्यक हो वहां वाहन कतार में लगाना। नागरिक कर्तव्य के अंतर्गत नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे विभिन्न करों का भुगतान समय पर करें एवं सही राशि का भुगतान करें। यह देश की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। यदि समस्त नागरिक अपने इस कर्तव्य का पालन करते हैं तो भारत में करों की दरों को निश्चित ही और अधिक नीचे लाया जा सकता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा एवं रखरखाव करना भी नागरिकों का परम कर्तव्य है, जैसे सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बनाए रखना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। कभी कभी आम जनता को गुमराह कर आंदोलन हिंसक रूप लेते नजर आते हैं एवं परिणामस्वरूप देश में आगजनी, लूटपाट और राष्ट्रीय सम्पदा की हानि देखने को मिलती है।

अभियान

चन्द्र–मंगल का अग्नि–जल संगम: एक मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और जीवन-परिवर्तक कथा

वैदिक ज्योतिष में किसी भी दो ग्रहों का संयोग केवल दो खगोलीय बिंदुओं का मेल नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा मानसिक और ऊर्जा-स्तर का कम्पन पैदा करता है जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन की हर परत तक जाता है। पर जब बात चन्द्रमा और मंगल की आती है, तो यह संयोग साधारण नहीं रह जाता। चन्द्रमा—जो मन, भावनाओं, स्मृतियों, संवेदनशीलता और मानसिक तरंगों का स्वामी है—जब मंगल की ज्वालामुखी-सी ऊर्जा, साहस, क्रोध और कर्म-प्रेरणा के साथ एक घर में आकर बैठता है, तब जातक के जीवन में एक विराट हलचल जन्म लेती है। यह हलचल कभी प्रगति का तूफान बनती है और कभी अशांति का भूकंप।

यह योग व्यक्ति के जीवन के बीचोंबीच एक अग्नि–जल का संगम बनाता है—जहाँ मन जल है और ऊर्जा आग। और आग और जल जब एक ही पात्र में डाल दिए जाते हैं, तो या तो भाप बनती है जो बाद में पानी बरसाती है, या फिर उबाल बनता है जो सबकुछ जला सकता है।

चन्द्रमा को शांत माना गया है—वह माँ की तरह पोषक है, कोमल है, चिंतनशील है, स्वप्निल है। यह ग्रह भीतर की दुनिया की नींव है। वहीं मंगल योद्धा है—निष्कपट परंतु तेज़, आवेगी परंतु न्यायप्रिय, कभी सुरक्षा देने वाला, कभी युद्ध छेड़ देने वाला। जब इन दोनों का मेल होता है, व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि उसका मन हर समय सक्रिय रहता है—या तो अवसर खोजता है या खतरे को पहचानता है। ये लोग अचानक निर्णय ले सकते हैं, अचानक व्यापार बदल सकते हैं, अचानक निवेश कर सकते हैं, अचानक स्थानांतरण कर सकते हैं। उनके जीवन की कहानी हमेशा स्थिर नहीं रहती; वह नदी की तरह निरंतर बहती और दिशा बदलती है।

इस योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जातक का दिमाग बहुत तीव्र होता है। उसकी स्मरणशक्ति प्रबल होती है, और किसी बात को टालने की प्रवृत्ति कमजोर होती है। वह जानता है कि किस व्यक्ति से कब बात करनी है, कब सौदा करना है, कब झुकना है, कब भिड़ना है। बहुत से सफल व्यापारी और नेता इसी योग के प्रभाव में अत्यधिक धनवान और प्रभावशाली बने हैं। पंचम भाव में चन्द्र–मंगल के संयोग ने कई लोगों को बुद्धि-वैभव, रचनात्मकता और अद्भुत व्यापारिक कौशल दिया है। दशम भाव में यह योग किसी व्यक्ति को ख्याति, शक्ति, प्रभाव, नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता देता है।

इतिहास में कई शक्तिशाली व्यक्तियों की कुंडलियों में यही योग पाया गया है—ऐसा योग जो व्यक्ति को “विचारों का युद्ध” और “कर्मों का युद्ध”—दोनों जीतने की क्षमता देता है।

लेकिन यही योग जब अशुभ दशाओं में, पीड़ित चन्द्रमा या दूषित मंगल के साथ बनता है, तभी इसी शक्तिशाली संयोजन की छाया उलटी दिशा में बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति के मन में बेचैनी घर कर सकती है। वह गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाता। वह छोटी बात को बड़ा विवाद बना सकता है। कभी-कभी यह योग व्यक्ति के भीतर एक “भीतरी आग” पैदा कर देता है—एक तेज़ बेचैनी जो उसे चैन नहीं लेने देती। वह अपनी ऊर्जा को संतुलित न कर पाए तो खुद को ही नुकसान पहुँचाने वाले निर्णय ले लेता है।

दशम भाव में यह योग अशुभ हो जाए तो जातक गलत मार्ग से धन कमाने की कोशिश कर सकता है। समाज में ऐसे कई लोग मिले हैं जिन्होंने अवैध व्यापार, तस्करी, हथियारों के सौदे, ब्लैक मार्केट या अनैतिक संबंधों के माध्यम से धन कमाया—उनके भीतर चन्द्र–मंगल का यही विकृत रूप सक्रिय था। उनकी ऊर्जा जहाँ सदाचार में खर्च हो सकती थी, वहाँ वह लोभ और तामसिक मार्गों में बह गई। कुछ लोग तो अपने ही परिवार के सदस्यों को गलत रास्तों पर धकेलते देखे गए—ऐसा अमंगलकारी संयोजन बनने पर घर का सुख नष्ट होता है और व्यक्ति अपने ही प्रियजनों का विरोधी बन जाता है।

चतुर्थ भाव में अशुभ चन्द्र–मंगल वैवाहिक जीवन में विस्फोट लाता है। पति-पत्नी के बीच ऐसी उग्र मनोवैज्ञानिक टकराहटें होती हैं कि झगड़े सामान्य से बढ़कर मानसिक हिंसा और कभी-कभी शारीरिक हिंसा में बदल सकते हैं। ऐसे लोगों के घर में शांति बहुत मुश्किल से टिक पाती है। मन की लहरों और ऊर्जा की आग—दोनों को संभालना इन संबंधों के लिए एक कठिन चुनौती बन जाता है।

प्रथम भाव में जब चन्द्रमा शुभ और मंगल अशुभ हो, तब मन कमजोर और ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। ऐसे लोग अवसाद, चिंता, अनिद्रा, भय और मानसिक असंतुलन जैसी स्थितियों का सामना कर सकते हैं। परंतु जब मंगल शुभ और चन्द्रमा अशुभ हो, तो जातक अक्सर गलत निर्णयों की ओर आकर्षित होता है—उसके कर्म आक्रामक और अनैतिक हो सकते हैं। उसकी महत्वाकांक्षा उसे ऐसे रास्तों पर ले जा सकती है जहाँ शक्ति तो मिलती है पर शांति नहीं।

लेकिन इस योग की असली आध्यात्मिक गहराई उससे भी आगे है। चन्द्र–मंगल योग आपको यह सिखाता है कि मन और ऊर्जा—दोनों को मिलाकर चलाना ही जीवन का रहस्य है। केवल भावनाओं से जीवन नहीं चलता और केवल बल से भी नहीं। दोनों का संयम, दोनों का संतुलन, दोनों की दिशा—यही जीवन का असली वास्तु है। इस योग वाले लोग यदि साधना करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें या आध्यात्मिक मार्ग पर चलें, तो उनकी मानसिक शक्ति और ऊर्जा इतनी प्रबल हो सकती है कि वे असंभव कार्य कर दिखाएँ। यह योग मनोबल और कर्मबल का मेल है—एक दिव्य संयोजन जो नियंत्रित होकर वरदान और अनियंत्रित होकर अभिशाप बन सकता है।

इसलिए किसी कुंडली में चन्द्र–मंगल योग को देखकर तुरंत निर्णय नहीं करना चाहिए। पहले यह देखना चाहिए कि चन्द्रमा कितना शांत है, कितना पीड़ित है, कितना स्थिर है। फिर देखना चाहिए कि मंगल न्यायप्रिय है या उग्र, संतुलित है या हिंसक, शुभ है या दूषित। योग किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किस ग्रह की दृष्टि है, किन ग्रहों की दशा चल रही है—इन सबके आधार पर ही यह तय किया जा सकता है कि यह योग जीवन में क्या कहानी लिखेगा।

अंत में यही कहा जा सकता है कि चन्द्र–मंगल योग एक ऐसा दर्पण है जिसमें व्यक्ति का मन भी दिखता है और उसकी ऊर्जा भी। यह दर्पण कभी उजाला दिखाता है, कभी छाया। यह योग कभी चढ़ाव देता है, कभी उतार। लेकिन यह योग हमेशा निष्क्रिय नहीं रहता—यह जीवन की धारा में कोई न कोई हलचल अवश्य लाता है। यह व्यक्ति को या तो महान बना देता है या बहुत संघर्षपूर्ण।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वडनगर में ताना-रीरी महोत्सव का भव्य शुभारंभ कराया

▸▸ मुख्यमंत्री का संगीत कला की स्वदेशी विरासत के संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री कलापिनी कोमकली को ताना-रीरी संगीत सम्मान अवॉर्ड प्रदान किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय संस्कृति के 2000 वर्षों के इतिहास को संजोए बैठे वडनगर में ताना-रीरी महोत्सव 2025 का शनिवार को शुभारंभ कराया। यह महोत्सव खेल, युवा एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग अधीनस्थ गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी-गांधीनगर तथा मेहसाणा जिला प्रशासन के संयुक्त उपक्रम से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। शनिवार को महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री कलापिनी कोमकली को प्रतिष्ठित ताना-रीरी संगीत सम्मान अवॉर्ड प्रदान किया गया।

श्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि वडनगर की भूमि में ही कुछ ऐसा सत्व-तत्व रहा है कि अनादिकाल से यहाँ समर्पण एवं सेवा साधना की पराकाष्ठा विकसित हुई है। उन्होंने ताना-रीरी को अनमोल संगीत कला विरासत का उत्तम उदाहरण बताते हुए कहा कि उनकी तरह ही वडनगर के सपूत एवं विश्व नेता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी राष्ट्र प्रथम के भाव से कार्यरत रहकर देश तथा दुनिया के समक्ष सेवा साधना का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कला एवं स्थापत्य की इस नगरी के इतिहास को पुनर्जीवित करने के सफल आयाम का सूत्रपात किया है। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री की विरासत संवर्धन नीतियों का विवरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने जहाँ प्राथमिक शिक्षा ली, उसे प्रेरणा स्कूल के रूप में विकसित किया है। जहाँ उन्होंने बचपन में परिश्रम की पराकाष्ठा सृजित की, उस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है और मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा वडनगर की समग्र पुरातन विरासत को प्रस्तुत करने वाले

अत्याधुनिक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का भी वडनगर में निर्माण हुआ है।

स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत वडनगर में हुए विकास की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना अंतर्गत शर्मिष्ठा तालाब, ताना-रीरी पार्क, लटेरी वाव (बावड़ी), अंबाजी कोठा तालाब तथा फोर्ट वॉल का विकास किया जा रहा है, जबकि पौराणिक हाटकेश्वर मंदिर का इतिहास लोग जान सकें; इसके लिए लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया है।

श्री भूपेंद्र पटेल ने भारतीय संगीत विरासत की समृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि आज रोग के उपचार के लिए भी म्यूजिक थेरेपी का उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी विरासत का युगों तक जतन एवं संवर्धन करने का संकल्प किया है।

वर्ष 2047 में विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को कला-संस्कृति के साथ जोड़ते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि कला-संस्कृति की स्वदेशी विरासत का संरक्षण हो और आने वाली पीढ़ी को भी इस विरासत के जतन की प्रेरणा मिले।

मुख्यमंत्री ने सभी का आह्वान किया कि वडनगर की पवित्र धरती से इस कला-संस्कृति के जतन के साथ स्वदेशी अपना कर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध हों।

संगीत समारोह में अवॉर्ड विजेता सुश्री कलापिनी कोमकली, प्रसिद्ध सितार वादक श्री निलाद्री कुमार तथा गायिका सुश्री ईशानी दवे ने शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन तथा लोक गीतों की सुमधुर प्रस्तुति से वडनगर को संगीतमय बना दिया।

भक्त कवि नरसिंह मेहता की दोहित्री शर्मिष्ठा की सुपुत्रियों ताना तथा रीरी ने मल्हार राग गाकर संगीत सम्राट तानसेन के दीपक राग से उत्पन्न हुए दाह को शांत किया था। उसकी स्मृति में तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2003 में ताना-रीरी महोत्सव तथा वर्ष 2010 में ताना-रीरी संगीत सम्मान अवॉर्ड की शुरुआत की गई थी।

ताना-रीरी महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर केबिनेट मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी व श्री ऋषिकेश पटेल, सामाजिक अग्रणी श्री सोमाभाई मोदी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री तृषाबेन पटेल, विधायक सर्वश्री के. के. पटेल (ऊंझा), सरदारभाई चौधरी (खेरालू), सुखाजी ठाकोर (बहुचराजी), राजेन्द्र चावडा (कडी), वडनगर नगर पालिका अध्यक्ष सुश्री मितिका शाह, गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार पांडे, जिला कलेक्टर श्री एस. के. प्रजापति, जिला विकास अधिकारी डॉ. हसरत जैस्मीन, गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी के सदस्य सचिव श्री आई. आर. वाळा, निवासी अपर कलेक्टर श्री जसवंत जेगोडा सहित वडनगर व मेहसाणा के अग्रणी तथा बड़ी संख्या में नगरजनों ने सुमधुर संगीत का आनंद उठाया।

पश्चिम रेलवे की फर्जी टिकटों पर सख्त कार्रवाई,अक्टूबर & नवंबर 2025 में कई मामलों का पता लगाया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षित, पारदर्शी व निष्पक्ष यात्रा सुनिश्चित करने के लिए फर्जी टिकटिंग के विरुद्ध अपनी सतर्कता को और मजबूत किया है। अक्टूबर–नवंबर 2025 के दौरान पश्चिम रेलवे के सतर्क टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा नकली मोबाइल टिकट, नकली आरक्षित टिकट तथा रियायतों के दुरुपयोग से जुड़े चार महत्वपूर्ण मामले पकड़े गए।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सभी मामलों में सख्त कार्रवाई की गई तथा संबंधित यात्रियों को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु जीआरपी के सुपुर्द किया गया।

पहले मामले में टिकट चेकिंग स्टाफ प्रदीप कुमार ने ए.सी. उपनगरीय लोकल में एक डिजिटल रूप से संपादित मोबाइल टिकट पकड़ा, जिसमें 15/- के टिकट को डिजिटल एडिटिंग टूल्स का उपयोग कर फर्जी तरीके से सीज़न टिकट में बदल दिया गया था। नियमित चेकिंग के दौरान यह हेरफेर सामने आया, जिसके बाद यात्री को हिरासत में लेकर जीआरपी के हवाले

किया गया।

दूसरा मामला टिकट चेकिंग स्टाफ मोहम्मद जाहिद कुरैशी द्वारा एक लंबी दूरी की ट्रेन में पकड़ा गया। रियायत के लिए अपात्र दो यात्री विकलांग कोटा में बुक किए गए टिकटों पर यात्रा कर रहे थे। रियायत का लाभ लेने के लिए किराया विवरण में छेड़छाड़ की गई थी, जबकि यात्री इसके पात्र नहीं थे। दोनों यात्रियों को तुरंत जीआरपी को सौंप दिया गया।

तीसरा मामला टिकट चेकिंग स्टाफ मोहम्मद जाहिद कुरैशी और अब्दुल अज़ीज़ द्वारा संयुक्त रूप से एक मेल/एक्सप्रेस ट्रेन में पकड़ा गया। एक नकली तत्काल आरक्षित टिकट, जो एक अनधिकृत एजेंट से अधिक दर पर खरीदा गया था, जांच के दौरान पाया गया। यात्री ने इसे अवैध तरीके से प्राप्त करने की बात स्वीकार की, जिसके बाद उसे जीआरपी के सुपुर्द किया गया।

चौथे मामले में टिकट चेकिंग स्टाफ साई प्रसाद ने ए.सी. उपनगरीय लोकल में डिजिटल रूप से संपादित मोबाइल टिकट पकड़ा। इसमें क्यूआर कोड और प्रमुख टिकट विवरणों से अनधिकृत ग्राफिक टूल्स का उपयोग कर छेड़छाड़ की गई थी। निरीक्षण में टिकट फर्जी पाए जाने के बाद संबंधित यात्री को हिरासत में लेकर जीआरपी कर्मियों को सौंप दिया गया।

पश्चिम रेलवे की यात्रियों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत माध्यमों, जैसे यूटीएस ऐप, आईआरसीटीसी ऐप, पीआरएस/यूटीएस बुकिंग काउंटर आदि से ही टिकट खरीदें, ताकि वास्तविक यात्रा दस्तावेज सुनिश्चित हों तथा फर्जीवाड़े से बचाव हो सके।

मेलोडी मेकर्स ग्रुप ने 'म्यूज़िक मौज मस्ती' से की नव वर्ष की शानदार शुरुआत!

(जीएनएस)। मेलोडी मेकर्स ने दीपावली के बाद इस नव वर्ष में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत 'म्यूज़िक मौज मस्ती' टाइटल से की और श्रोताओं का मन जीता। गीत-संगीत के इस शानदार कार्यक्रम में सभी कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दीं। मेलोडी मेकर्स ग्रुप का प्रयास हमेशा यह रहता है कि उम्र कोई भी हो, कलाकार को सम्मान और एक अच्छा मंच दिया जाए। साथ ही, कला के प्रति समर्पण भाव रखने वाले श्रोताओं का ध्यान रखते हुए ही कार्यक्रम किए जाएं। अपने नौवें वर्ष में मेलोडी मेकर्स ग्रुप इसी प्रयासों में लगातार निरंतर सफलतापूर्वक अग्रसर है।

तिरुपति बालाजी मंदिर में बड़ा घी घोटाला 20 करोड़ लड्डुओं में मिलावट का खुलासा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) में लड्डू प्रसाद के निर्माण में बड़े पैमाने पर मिलावट का मामला सामने आया है। ट्रस्ट बोर्ड की जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि 2019 से 2024 के बीच बनाए गए लगभग 48.76 करोड़ लड्डुओं में से करीब 20 करोड़ लड्डुओं में शुद्ध घी की जगह मिलावटी घी का इस्तेमाल किया गया। यह खुलासा लड्डू उत्पादन, घी की खरीद और वितरण के रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद हुआ। जांच में सामने आया कि इन लड्डुओं में इस्तेमाल किया गया 68 लाख किलो घी मिलावटी था, जिसमें पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और अन्य मिलावटी पदार्थ शामिल थे। इस घी को उत्तराखंड की भोले बाबा डेयरी और उसकी सहायक कंपनियों से खरीदा गया था। इस घी की बाजार कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। पिछले पांच वर्षों में बनाए गए इन लड्डुओं को लगभग 11 करोड़ श्रद्धालुओं

को प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस श्रद्धालु को शुद्ध लड्डू मिला और किसे मिलावटी। यहां तक कि VVIP के लिए बनाए जाने वाले अलग पैक भी पहचान से बाहर थे। घोटाले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की नेतृत्व वाली विशेष जांच टीम (SIT) कर रही है। SIT ने हाल ही में पूर्व TTD चेयरमैन और YSRCP सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी से लगभग आठ घंटे पूछताछ की। इस दौरान रेड्डी ने दावा किया कि उन्हें लैब रिपोर्ट की जानकारी नहीं दी गई थी और घी की खरीद व्यवस्था तकनीकी समिति की सिफारिशों के अनुसार की गई थी। उनके पूर्व सहायक चिन्ना अप्पन्ना को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि पूर्व एक्जीक्यूटिव ऑफिसर एवी धर्मा रेड्डी से भी पूछताछ हो चुकी है।

SIT ने अपनी मुख्य रिपोर्ट नेल्लोर की अदालत में जमा कर दी है और माना जा रहा है कि 15 दिसंबर तक पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इस घोटाले ने मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता और श्रद्धालुओं के विश्वास पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है ताकि भविष्य में धार्मिक स्थलों पर ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। इस खुलासे ने देशभर में सनसनी फैला दी है और श्रद्धालुओं में नाराजगी और चिंता दोनों को जन्म दिया है। मामले की जांच अभी जारी है और SIT की अगली कार्रवाई पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं।

राज्य के किसानों से सोमवार 24 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान, बाजरे, ज्वार, मक्के, रागी की सीधी खरीद शुरू की जाएगी

▸▸ राज्य में निर्धारित केन्द्रों से 31 जनवरी, 2026 तक खरीद करने के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के एक और संवेदनशील निर्णय की कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने की घोषणा

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य सरकार सोमवार 24 नवंबर से खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 अंतर्गत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान, बाजरे, ज्वार, मक्के तथा रागी की सीधी खरीद करेगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपना कर बेमौसम बारिश से भारी नुकसान झेलने वाले किसानों को उबारने के लिए हाल ही में 10 हजार करोड़ रुपए का ऐतिहासिक राहत पैकेज दिया है।

अब श्री पटेल ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 अंतर्गत धान, बाजरे, ज्वार, मक्के तथा रागी की सीधी खरीद का किसान एवं गरीब कल्याणकारी निर्णय किया है।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने शनिवार को राजकोट में यह घोषणा करते हुए कहा कि धान के लिए प्रति हेक्टेयर 1500 किलोग्राम धान पंजीकृत किसानों से खरीदा जाएगा।

उन्होंने जोड़ा कि सोमवार 24 नवंबर से आगामी 31 जनवरी 2026 तक इस खरीद अंतर्गत धान के लिए राज्यभर में 113 खरीद केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा बाजरे के लिए 150, ज्वार के लिए 50, मक्के के लिए 82 तथा रागी के लिए 19 केन्द्र निर्धारित किए गए हैं, जहाँ से खरीद होगी।

उन्होंने आगे कहा कि इस खरीद अंतर्गत बाजरा प्रति हेक्टेयर 1848 किलोग्राम,

ज्वार प्रति हेक्टेयर 1539 किलोग्राम, मक्का प्रति हेक्टयर 1864 किलो तथा रागी प्रति हेक्टेयर 903 किलोग्राम के अनुसार खरीदा जाएगा।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रति क्विंटल खरीद का जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, उसमें धान के लिए प्रति क्विंटल 2369 तथा 2389, बाजरे कि लिए 3075, ज्वार (हाइब्रिड) के लिए 3999, ज्वार (मालदंडी) के लिए 4049, मक्के के लिए 2400 और रागी के लिए 5186 रुपए मूल्य रहेगा।

समर्थन मूल्य पर बड़े पैमाने पर आ रही उपजों को खरीद कर राज्य के एनएफएसए तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत समाविष्ट किए गए 74 लाख परिवारों के 3.60 करोड़ लोगों को निःशुल्क वितरण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा किए गए इस किसान एवं गरीब हितकारी निर्णय के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी ने उनका आभार व्यक्त किया है।

यूरोप के बाजारों में पहुँचा भारत का यूपीआई, अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने की तैयारी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। वैश्विक वित्तीय ढांचे में भारत की डिजिटल भुगतान क्षमता एक नया इतिहास रचने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर वह कदम उठाया है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं की थी। दुनिया का सबसे तेज़ और सस्ता डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई अब यूरोप के इंस्टैंट पेमेंट प्लेटफॉर्म TIPS (टार्गेट इंस्टैंट पेमेंट सेटलमेंट) से जुड़ने की तैयारी में है। यह घोषणा तभी से चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि इससे यूरोप में घूमने वाले लाखों भारतीयों को नकदी, कार्ड और भारी शुल्क वाले विदेशी भुगतान विकल्पों से राहत मिलने वाली है।

परियोजना अब "रियलाइजेशन फेज़" में दाखिल हो चुकी है, जिसका अर्थ है कि दोनों ओर के तकनीकी विशेषज्ञ, नियामक संस्थाएँ और साइबर सुरक्षा टीमें एक ऐसी प्रणाली तैयार कर रही हैं जो यूरोप के किसी भी बड़े शहर—from पेरिस की गलियों से लेकर रोम के ऐतिहासिक केंद्र तक और मैड्रिड के व्यस्त बाजारों तक—भारतीय यात्रियों को केवल अपने मोबाइल फोन से "स्कैन एंड पे" की सुविधा देगी। जैसे भारत में छोटे ठेलों से लेकर बड़े मॉल तक यूपीआई स्वीकार करते हैं, उसी तरह भविष्य में यूरोपीय दुकानदार, रेस्टोरेंट, कैफे, होटल, टैक्सी चालक और पर्यटन सेवाएँ भारतीय QR कोड को स्वीकार कर सकेंगे।

यह सुविधा लागू होने के बाद भारतीयों को यूरोप में यात्रा करते समय न तो कार्ड के अंतरराष्ट्रीय शुल्क का डर रहेगा और न ही कैश निकालने के लिए एटीएम ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। भुगतान तुरंत होगा, शुल्क बेहद कम होंगे और लेन-देन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। दिलचस्प बात यह भी है कि अब यूरोप आने वाले भारतीयों की तरह भारत आने वाले यूरोपीय नागरिक भी यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे, जो वैश्विक डिजिटल भुगतान प्रणाली में भारत को एक अग्रणी भूमिका दिलाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञ इसे केवल वित्तीय सेवा का विस्तार नहीं, बल्कि एक डिजिटल कूटनीति की सफलता भी बताते हैं। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की वार्ताएँ अंतिम चरण में हैं और यूपीआई–TIPS कनेक्टिविटी इस नए आर्थिक रिश्ते को और मजबूत करेगी। यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम अत्यधिक विनियमित और सावधान माना जाता है, ऐसे में उसका भारत के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म से जुड़ना भारत की तकनीकी विश्वसनीयता और साइबर सुरक्षा क्षमता का प्रमाण माना जा रहा है।

वित्तीय विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह पहल उन छोटे–मध्यम व्यापारियों को भी बड़ी राहत देगी जो अंतरराष्ट्रीय ग्राहक सेवा से जुड़े हैं। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय भुगतान में कई तरह के शुल्क, विनिमय दरें और लंबी सेटलमेंट प्रक्रियाएँ मुश्किल पैदा करती हैं। यूपीआई के जुड़ने से ये प्रक्रियाएँ सरल, पारदर्शी और सस्ती होंगी। परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, तकनीकी एकीकरण, साइबर सुरक्षा ढांचे, बैंकिंग अनुपालन और यूरोप के विभिन्न देशों की नीतियों के अनुसार अनुकूलन की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। उम्मीद है कि सभी चरणों को पूरा करने के बाद यह सुविधा 2026 की पहली छमाही में आम उपयोगकर्ताओं के लिए शुरू हो जाएगी। यह कदम न केवल यात्रियों के जीवन को आसान बनाएगा, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूत, प्रभावी और आकर्षक बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नई नियुक्ति पाने वाले 4400 से अधिक युवाओं का आह्वान

राज्य सरकार में मिले नौकरी के अवसर को केवल नियुक्ति के रूप में नहीं, बल्कि आम आदमी की सेवा से राष्ट्र निर्माण में योगदान के अवसर के रूप में स्वीकारें

-: मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

▸▸ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुड गवर्नेंस के लिए ट्रांसपरेंसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग तथा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर जो फोकस किया है, उसे गुजरात ने सरकार के विभिन्न विभागों में पारदर्शी नियुक्ति से साकार किया है

▸▸ राज्य सरकार द्वारा कार्यरत किया गया कैडर मैनेजमेंट पोर्टल तथा 10 वर्षीय भर्ती कैलेंडर भविष्य के मैन पावर रिक्रूमेंट आयोजन के लिए महत्वपूर्ण बना है

▸▸ राज्य सरकार के विभिन्न संवर्गों में वर्ग-3 में नई नियुक्ति प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का गौरवशाली समारोह गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा मंत्रियों की उपस्थिति में संपन्न

▸▸ उप मुख्यमंत्री का राज्य के नागरिकों की सेवा के लिए मिले अवसर का उपयोग नागरिकों की आशाएँ परिपूर्ण करने तथा सकारात्मकता से हो; इसका ध्यान रखने का अनुरोध

▸▸ इस महीने के अंत तक गुजरात पुलिस बल में कुल 14,507 नई रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया घोषित की जाएगी : उप मुख्यमंत्री

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के विभिन्न संवर्गों में वर्ग-3 में नई नियुक्ति प्राप्त कर रहे 4,473 युवाओं का आह्वान किया है कि वे राज्य सरकार की सेवा में उन्हें मिले अवसर को केवल नई नियुक्ति के रूप में नहीं, बल्कि आम आदमी की सेवा से राष्ट्र निर्माण में योगदान के अवसर के रूप में स्वीकारें।

इस संदर्भ में श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार में 'नागरिक देवो भवः' का मंत्र अपनाया है और लोगों को गुड गवर्नेंस की निरंतर प्रतीति कराई है। उन्होंने कहा कि नई नियुक्ति पा रहे युवाओं से अपेक्षा है कि वे भी प्रामाणिकता के साथ कार्यरत रहकर, किसी छोटे आदमी की मुश्किल दूरकर या किसी विधवा माता के आँसू पोंछकर तथा निराधार का आधार बनकर अपने वाणी-बर्ताव एवं व्यवहार से लोगों को संवेदनशील सरकार की अनुभूति कराएँ।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की विशेष उपस्थिति में शनिवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 'विकसित भारत, विकसित गुजरात' अंतर्गत गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन मंडल (गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ड यानी जीएसएसएसबी) द्वारा सरकार के विभागों में विभिन्न कैडर में चयनित कुल 4,473 उम्मीदवारों में से लगभग 21 उम्मीदवारों को

सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए।

इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री रमणभाई सोलंकी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रेरणा देते हुए कहा कि वे ड्यूटी और कार्य में शिथिलता नहीं, बल्कि नवीनता के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रहित प्रथम एवं राज्य के विकास से राष्ट्र के विकास के भाव को समग्र कॅरियर में प्राथमिकता देकर 2047 के विकसित भारत के निर्माण के संवाहक बनें।

श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुड गवर्नेंस के लिए ट्रांसपरेंसी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर जो फोकस किया है, उसे गुजरात ने पारदर्शी नियुक्ति से साकार किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन के लिए टेक्नोलॉजी के उपयोग से कार्यरत किए गए 3000 से अधिक कैडर की जानकारी से युक्त कैडर मैनेजमेंट पोर्टल तथा 10 वर्षीय भर्ती कैलेंडर का विवरण दिया। इसके परिणामस्वरूप मैन पावर रिक्रूटमेंट का आयोजन सरल बना है। रोजगार वांछु युवाओं को भी परीक्षा की अग्रिम जानकारी मिलती है और वे पूर्ण तैयारी कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने जोड़ा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुए रोजगार मेलों से देश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के अतिरिक्त निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में 'हर हाथ को काम, हर काम का सम्मान' का ध्येय साकार करने वाले रोजगार के अवसर खुले हैं तथा 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री के विजन से 'पीएम विकसित भारत योजना' शुरू हुई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने नई नियुक्ति पा रहे युवाओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित कीं।उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का गुजरात सरकार परिवार में स्वागत-सह-अभिनंदन करते हुए कहा कि आज का दिन गुजरात की युवा शक्ति के लिए एक स्वर्णिम दिवस है। आज जब सभी उम्मीदवारों ने अथक परिश्रम के अंत में यह उपलब्धि प्राप्त की है, तब उनके माता-पिता एवं परिवार के सदस्यों के सपने भी साकार हुए होंगे। यह सफलता जनसेवा की नई शुरुआत है। नई नियुक्ति पाने वाले सभी उम्मीदवारों को राज्य के नागरिकों के काम करने के लिए अवसर मिला है। उन्होंने इस अवसर का उपयोग नागरिकों की सेवा करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हो; इसका ध्यान रखने का अनुरोध किया।

श्री संघवी ने कहा कि अप्रैल-2025 से अब तक गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन मंडल द्वारा लगभग 101 परीक्षाएँ आयोजित कर रिकॉर्ड बनाया गया है। उन्होंने ऑनलाइन, पारदर्शी एवं त्वरित भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने वाले गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन मंडल की समग्र टीम को अभिनंदन दिया।

उन्होंने इस अवसर पर महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियाँ करने वाले राज्य के लाखों युवाओं के लिए इसी महीने के अंत तक गुजरात पुलिस बल में 14,507 नई रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया घोषित की जाएगी। इनमें पुलिस उप निरीक्षक (पीएसआई) तथा लोकरक्षक जैसे मुख्य कैडर की 13,591 रिक्तियाँ तथा टेक्निकल कैडर की 916 रिक्तियाँ शामिल हैं। इसके अलावा, हाल में गुजरात पुलिस बल की 12 से अधिक रिक्तियों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है, जिसके नियुक्ति पत्र भी शीघ्र दिए जाएंगे।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संदेश के माध्यम से नवनियुक्त उम्मीदवारों को अभिनंदन देकर 'विकसित भारत' के लिए अपना अधिकतम योगदान देने की शुभकामनाएँ दीं। मुख्य सचिव श्री एम. के. दास ने स्वागत संबोधन में कहा कि प्रत्येक युवा का सरकारी नौकरी प्राप्त करने का एक सपना होता है और आज का दिन उस सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन मंडल द्वारा यह भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी ढंग से करके सभी चरणों में आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी समय में आँगनबाड़ी तथा पुलिस विभाग में निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने नवनियुक्त उम्मीदवारों को अभिनंदन देते हुए कहा, "आप सभी भाग्यशाली हैं कि राज्य सरकार की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के कालखंड के दौरान आपकी भर्ती हो रही है। आपके कार्यकाल में भारत विकास की नई दिशाएँ पार करने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सब इसमें अपना अधिकतम योगदान देंगे।"

राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि ने इस अवसर पर उपस्थित सभी का आभार व्यक्त कर नवनियुक्त उम्मीदवारों को शुभकामनाएँ दीं। राज्यभर से चयनित उम्मीदवारों में सर्वाधिक जूनियर क्लर्क वर्ग-3 में 2828 के अलावा सब रजिस्ट्रार ग्रेड 1-2 की कुल 92, स्टाम्प निरीक्षक वर्ग-3 की कुल 22, वरिष्ठ लिपिक वर्ग-3 की 339, प्रधान लिपिक वर्ग-3 की 138, सहायक समाज कल्याण अधिकारी वर्ग-3 की कुल 20, समाज कल्याण निरीक्षक वर्ग-3 की 144, गृहपति, कार्यालय सहायक, आगार प्रबंधक, सहायक आगार प्रबंधक, सहायक आदिजाति विकास अधिकारी वर्ग-3, लेखपाल वर्ग-3 तथा सर्वेक्षक की कुल 882 सहित कुल 4473 रिक्तियाँ शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन मंडल के अध्यक्ष श्री तुषार धोळकिया, सामान्य प्रशासन विभाग सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में उम्मीदवार उपस्थित रहे।

आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कांफ्रेंस बनेगा मोरबी सिरेमिक क्लस्टर के लिए नए वैश्विक अवसरों का द्वार

- मोरबी सिरेमिक क्लस्टर है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिरेमिक उत्पादन हब
- भारत-यूके CETA समझौते के तहत मोरबी के प्रमुख सिरेमिक निर्यातों को मिलेगी शून्य-शुल्क और टैरिफ-रहित बाजार की सुविधा
- FY 2024-25 में यूके को भारतीय सिरेमिक निर्यात तीन गुना बढ़कर 110 मिलियन डॉलर तक पहुँचा, जिसमें मोरबी का योगदान 65% (71.6 मिलियन डॉलर)
- मोरबी सिरेमिक क्लस्टर ने किए 3.5 लाख प्रत्यक्ष और करीब 10 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित
- आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कांफ्रेंस में मोरबी सिरेमिक की वैश्विक संभावनाओं और स्थानीय उद्यमिता को प्रदर्शित करने का मिलेगा अवसर

(जीएनएस)। गांधीनगर : गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र का मोरबी सिरेमिक क्लस्टर वैश्विक सिरेमिक उद्योग में एक नई पहचान गढ़ रहा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सिरेमिक उत्पादन क्लस्टर के रूप में मोरबी आज अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहाँ 800 से अधिक निर्यात-उन्मुख यूनिट्स इसे एक सशक्त वैश्विक हब बनाती हैं। विकास और उद्यमशीलता के मजबूत इकोसिस्टम के साथ मोरबी क्लस्टर गुजरात की "विकसित भारत@2047" की यात्रा में निर्णायक भूमिका निभा रहा है और विश्वभर से बढ़ती सिरेमिक उत्पादों की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है।

यूके में भारतीय सिरेमिक की बढ़ती मांग, मोरबी ने संभाला नेतृत्व

पिछले 3-4 वर्षों में भारतीय सिरेमिक निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और यूके को निर्यात तीन गुना बढ़कर FY 2024-25 में 110 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया है, जिसमें मोरबी अकेले 65% यानी 71.6 मिलियन डॉलर का योगदान देता है। यह तेज़ वृद्धि यूके बाज़ार में पोर्सिलेन स्लैब, टाइल्स और क्वार्ट्ज उत्पादों जैसी प्रीमियम निर्माण सामग्रियों की बढ़ती मांग को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

सिरेमिक क्षेत्र की संभावनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, जिन्हें शहरीकरण की तेज़ रफ्तार, सरकारी आवास योजनाएँ और स्वच्छ भारत मिशन जैसी पहलों से और बल मिल रहा है। मोरबी का सिरेमिक और सैनिटरीवेयर उद्योग वॉल और फ्लोर टाइलों से लेकर विभिन्न बाथरूम एक्सेसरीज़ तक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करता है। अपनी उत्कृष्ट उत्पादन क्षमता और निर्यात प्रदर्शन के आधार पर मोरबी को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सिरेमिक टाइल्स एवं सैनिटरीवेयर श्रेणी में "टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस" (TEE) का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और भी सशक्त हुई है।

मोरबी सिरेमिक क्लस्टर ने किए 3.5 लाख प्रत्यक्ष और करीब 10 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित

मोरबी का सिरेमिक क्लस्टर न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश में रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। यह क्लस्टर विनिर्माण इकाइयों में लगभग 3.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है और करीब 10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही उद्योग ने लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, कच्चे माल की आपूर्ति जैसी सहायक क्षेत्रों में भी नई नौकरियों का सृजन किया है। मोरबी सिरेमिक क्लस्टर ने न केवल स्थानीय आबादी को रोजगार प्रदान किया है बल्कि अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों के लिए भी व्यापक अवसर सुनिश्चित किए हैं, जिससे यह क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत बन रहा है।

"मेड इन मोरबी" बन रहा वैश्विक ब्रांड

एक छोटे से शहर से वैश्विक निर्यातक बनने की यात्रा में मोरबी सिरेमिक क्लस्टर ने गुजरात को निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने के साथ-साथ "मेड इन मोरबी" को एक वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। मोरबी सिरेमिक उद्योग को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से विशेष लाभ मिला जिसकी अवधारणा 2003 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तैयार की गई थी। कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में आयोजित होने वाला आगामी वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन मोरबी सिरेमिक क्लस्टर की संभावनाओं और स्थानीय उद्यमियों की ऊर्जा को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का अवसर प्रदान करेगा। यह प्रतिष्ठित आयोजन निवेश को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र की स्थानीय प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

भारत-यूके आर्थिक समझौता मोरबी सिरेमिक उद्योग के लिए बना नए अवसरों का द्वार

भारत सिरेमिक उत्पादों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और वैश्विक बाज़ारों में अपनी मज़बूत पकड़ के साथ मोरबी इस क्षेत्र का प्रमुख आधार स्तंभ बनकर उभरा है। 24 जुलाई 2025 को भारत-यूके कोम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) पर हुए हस्ताक्षर गुजरात की औद्योगिक क्षमता और मोरबी सिरेमिक क्लस्टर के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यह ऐतिहासिक समझौता भारत के प्रमुख सिरेमिक निर्यातों के लिए शून्य-शुल्क और टैरिफ-रहित बाज़ार पहुँच सुनिश्चित करता है, जिससे मोरबी के उत्पादों के लिए यूके समेत वैश्विक बाज़ारों में नई संभावनाएँ खुल रही हैं।

तीन महाद्वीप, एक संकल्पः भारत–ऑस्ट्रेलिया–कनाडा ने मिलकर रचा प्रौद्योगिकी सहयोग का नया इतिहास

(जीएनएस)। जोहानिसबर्ग। दक्षिण अफ्रीका की धूप में नहाए जोहानिसबर्ग शहर ने शनिवार को वह ऐतिहासिक क्षण देखा, जब भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, तीन महाद्वीपों और तीन महासागरों से उठने वाली लोकतांत्रिक आवाजें, भविष्य की दुनिया के लिए एक नई तकनीकी साझेदारी का आधार तैयार करने बैठीं। जी-20 शिखर सम्मेलन के व्यस्त कार्यक्रमों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाते हुए एक त्रिपक्षीय गठबंधन की घोषणा की—एक ऐसा गठबंधन, जिसका उद्देश्य केवल तकनीकी सहयोग नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की दिशा बदलने का सपना भी है। इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने मिलकर एसीआईटीआई—यानी ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप—नाम की नई पहल की शुरुआत की है, जो आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग का अभूतपूर्व मंच बनेगी। इस साझेदारी को तीनों नेताओं ने न केवल राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया, बल्कि इसे 21वीं सदी की डिजिटल और वैज्ञानिक

क्रांति का साझा द्वार भी कहा।

समझा जा रहा है कि यह साझेदारी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के तेज़ विकास, कृत्रिम मेधा (AI) के सुरक्षित और व्यापक उपयोग तथा क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे उच्चस्तरीय शोध क्षेत्रों में मिलकर काम करने का रास्ता तैयार करेगी। भारत जहां अपनी विशाल तकनीकी प्रतिभा और नवाचार क्षमता के लिए जाना जाता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा, खनन, वैज्ञानिक अनुसंधान और उच्च शिक्षा संस्थानों की मजबूती के साथ इस सहयोग में गहराई जोड़ता है। दूसरी ओर कनाडा, जो AI और क्लीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व रखता है, इस गठजोड़ को एक मजबूत नवाचार त्रिकोण में बदल देता है।

जोहानिसबर्ग में हुई यह चर्चा केवल एक घोषणा नहीं, बल्कि आधुनिक विश्व व्यवस्था में लोकतांत्रिक देशों की साझा जिम्मेदारी का अहसास भी है। तीनों नेता इस बात पर सहमत दिखे कि उभरती प्रौद्योगिकियाँ सिर्फ आर्थिक प्रगति का माध्यम नहीं, बल्कि मानवता को सुरक्षित, समावेशी और टिकाऊ भविष्य देने का भी साधन हैं। वैश्विक परिदृश्य में जहां प्रौद्योगिकी का नियंत्रण नए राजनीतिक समीकरण बना रहा है, वहां यह त्रिपक्षीय पहल लोकतांत्रिक देशों के सहयोग की नई मिसाल मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात के दौरान इस साझेदारी को "भविष्य की पीढ़ियों का साझा निवेश" कहा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संतुलन और सहयोग बढ़ाने वाला कदम बताया, जबकि कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि तकनीक को मानवता की सेवा में लगाने का यह प्रयास दुनिया की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस साझेदारी से तीनों देशों के स्टार्टअप्स, शोध संस्थानों, तकनीकी कंपनियों और युवा उद्यमियों को बड़े स्तर पर लाभ मिलेगा। AI से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक, रक्षा तकनीक से लेकर साइबर सुरक्षा तक—कई क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएँ आने वाले महीनों में आकार ले सकती हैं। दुनिया जहां नई तकनीकी होड़ में विभाजित दिखती है, वहीं भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का यह कदम एक शांत, स्थिर और भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभर रहा है। जोहानिसबर्ग में हुए इस त्रिपक्षीय संवाद ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाला दशक केवल आर्थिक साझेदारियों का नहीं, बल्कि तकनीकी संकल्पों का दशक होगा। तीनों देशों ने यह संकेत दे दिया है कि वैश्विक राजनीति अब केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि कोड, चिप्स, डेटा, ऊर्जा और नवाचार की नीतियों से तय होगी। और इस नए युग में, भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने आज एक ऐसी साझेदारी की नींव रखी है जो आने वाले समय में वैश्विक तकनीकी सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बन सकती है।

मुरादाबाद में करोड़ों की GST चोरी का बड़ा गिरोह बेनकाब दो गिरफ्तार, फर्जी बिलिंग का राज्यव्यापी जाल उजागर

(जीएनएस)। मुरादाबाद। शनिवार की सुबह मुरादाबाद की सिविल लाइंस पुलिस, एसओजी और आईटी विभाग की संयुक्त टीम ने वह पर्दा उठा दिया, जिसके पीछे महीनों से सरकार की आंखों में धूल झोंककर करोड़ों रुपये की जीएसटी चोरी की जा रही थी। शहर की तंग गलियों से लेकर दिल्ली की बड़े स्तर पर सक्रिय फर्जी फर्म तैयार करने वाली मंडियों तक फैला यह नेटवर्क लंबे समय से ऑपरेट हो रहा था। टीम ने दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो न सिर्फ टैक्स चोरी के इस खेल के मुख्य खिलाड़ी थे, बल्कि पूरे गैंग की गतिविधियों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण कड़ी भी थे। आरोपियों के पास से 8 एटीएम कार्ड, 3 आधार कार्ड, फर्जी दस्तावेज और कई तकनीकी सबूत मिले हैं, जो इस बड़े फर्जीवाड़े की परतें खोलने के लिए पर्याप्त हैं।

गिरफ्तार किए गए लोगों के नाम हैं—इम्तियाज मलिक, निवासी शास्त्री नगर थाना नौचंदी मेरठ, और इफ्तेखार आलम उर्फ दानिश कबाड़ी, निवासी चमकनी गौरियापुर थाना रामचंद्र मिशन शाहजहांपुर। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने न केवल फर्जी फर्में खड़ी कीं, बल्कि फर्जी रजिस्ट्रेशन आईडी, ई-वे बिल और इनवॉइस बनाकर करोड़ों का व्यापार दिखाया, जबकि असलियत में न कोई माल खरीदा गया, न बेचा गया—सिर्फ बिलों की दुनिया में मौजूद एक अदृश्य कारोबार चलता रहा, जिसका एकमात्र उद्देश्य था—सरकारी खजाने को चूना लगाना और व्यक्तिगत संपत्ति का जाल बुनना।

पूछताछ में इम्तियाज मलिक ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह कभी टायर और वॉशिंग मशीन का वैध कारोबार करता था। लेकिन 2022 में कारोबार बंद होने और आर्थिक हालात बिगड़ने के बाद वह दिल्ली में सक्रिय फर्जी जीएसटी आईडी बनाने वाले गिरोह से जुड़ गया। यह गिरोह 50,000 से 1.5 लाख रुपये में तैयार कंपनियों के नाम पर फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ई-वे बिल और इनवॉइस उपलब्ध कराता था। इम्तियाज केवल एक 'कमीशन एजेंट' की तरह इस खेल में उतरा, लेकिन धीरे-धीरे वह पूरे रैकेट का महत्वपूर्ण ऑपरेटर बन गया।

जानकारी के अनुसार, इस गैंग के जरिए 6 करोड़ रुपये से अधिक का फर्जी लेन-देन दिखाया गया, जिसकी मदद से भारी टैक्स चोरी की गई। यही नहीं, इफ्तेखार आलम फर्जी फर्मों के बैंक खातों का संचालन करता था और उन्हीं खातों के जरिए पैसे की आवाजाही को वैध दिखाकर नेट बिना किसी भय के चलता रहा। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, बैंक आईडी—हर दस्तावेज को एक नई पहचान देकर इस्तेमाल किया जाता था। व्यापारी होने का भरपूर नाटक किया जाता था ताकि किसी की नजर इस अवैध कारोबार पर न जाए।

पुलिस की शुरुआती जांच कहती है कि इस गैंग ने अब तक लगभग 4 से 5 करोड़ रुपये की अवैध कमाई कर ली थी। तकनीकी सर्विलांस, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रेल की मदद से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती—यह रैकेट इससे कहीं बड़ा है। जांच में सामने आया है कि दिल्ली में बैठे कॉल सेंटर संचालक, दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले मध्यस्थ और फर्जी कंपनियां बनाने वाले डेटा ऑपरेटर भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। पुलिस अब इन सभी की तलाश में है।

फर्जी कंपनियों के सहारे की गई यह टैक्स चोरी न केवल एक बड़ा आर्थिक अपराध है, बल्कि यह बताती है कि किस तरह संगठित गिरोह तकनीकी संसाधनों का दुरुपयोग कर सरकारी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता कहा है, लेकिन साथ ही यह साफ कर दिया है कि मामला यहीं रुकेगा नहीं। आने वाले दिनों में इस नेटवर्क की और परतें हटेंगी और कई नए नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुट गई है। जीएसटी चोरी के इस हाई-टेक रैकेट का खुलासा पूरे प्रदेश में चल रहे उन लोगों के लिए भी चेतावनी है, जो फर्जी बिलिंग और अवैध लेन-देन के सहारे काला कारोबार चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुरादाबाद की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि ऐसे किसी भी खेल की उम्र अब लंबी नहीं होगी।

'आपके पास वोट, मेरे पास फंड'- अजित पवार के बयान से मचा राजनीतिक भूचाल, विपक्ष ने कहा लोकतंत्र का अपमान

(जीएनएस)। महाराष्ट्र। राज्य की राजनीति इन दिनों पूरी तरह गरमाई हुई है और इस बार विवाद की चिंगारी खुद राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार के एक बयान से उठी है। मालेगांव, बारामती में स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान पवार ने जो शब्द कहे, वह पल भर में राजनीतिक गलियारों में आग की तरह फैल गए। मंच के सामने खड़े हजारों लोगों की भीड़ में उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा—"आपके पास वोट हैं, मेरे पास फंड अगर आप हमारे 18 उम्मीदवारों को जिताएंगे, तो फंड की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप हमें नकारेंगे, तो हम भी आपको नकार देंगे।" यह वाक्य जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे महाराष्ट्र में एक नया विवाद खड़ा हो गया। अजित पवार का यह बयान न सिर्फ धमकी की तरह समझा गया, बल्कि इसे मतदाताओं के साथ सीधी सौदेबाजी माना गया—एक ऐसा सौदा जिसमें वोट के बदले फंड का लालच और दबाव दोनों मौजूद थे। आलोचकों का कहना है कि यह बयान लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत

है, जहां जनता को भयमुक्त होकर वोट देने का अधिकार हासिल है। लेकिन पवार के अंदाज ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या विकास योजनाओं का वितरण भी अब राजनीतिक पसंद-नापसंद का विषय बन गया है?

बयान सामने आते ही विपक्ष ने आक्रामक रुख अख़्तियार कर लिया। शिवसेना (यूबीटी) के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने कहा कि सरकारी फंड किसी नेता का निजी खजाना नहीं होता, न ही कोई मुख्यमंत्री या मंत्री इसे अपनी निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने पवार के बयान को 'मतदाताओं को धमकाने' जैसा बताया और पूछा कि चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा है? दानवे ने कहा कि टैक्सपेयर्स का पैसा नेता की मर्जी से नहीं चलता—वह जनता के अधिकार का पैसा है, जिसे बांटना किसी की दया नहीं, सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए यह बयान स्पष्ट रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है और आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। उसके नेताओं ने पवार पर लोकतंत्र को गिरवी रखने का आरोप लगाया और कहा कि चुनावों में जीतने के लिए नेताओं को जनता को डराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बयान को मंच से दी गई "सीधी धमकी" बताते हुए पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग को अब 'अजित पवार मॉडल' पर अपनी राय साफ करनी ही होगी। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है जब किसी नेता ने सत्ता के जरिए वोटरों पर दबाव बनाने की कोशिश की हो, लेकिन यह बयान इतनी स्पष्टता और कठोरता के साथ दिया गया कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा प्रहार महसूस होता है।

दूसरी तरफ, एनसीपी के भीतर भी हलचल मची है। अजित पवार जिस मालेगांव नगर पंचायत में यह भाषण दे रहे थे, वहां 2 दिसंबर को चुनाव होने हैं और यह इलाका पवार परिवार की दशकों पुरानी राजनीतिक जमीन माना जाता है। यहां हार किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। शायद इसी चिंता और दबाव के बीच यह बयान निकल गया, या फिर यह रणनीति का हिस्सा था—यह फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों के बीच बहस का विषय है। लेकिन इतना तय है कि बयान के बाद स्थानीय राजनीति में तनाव और बढ़ गया है।

मालेगांव बारामती का ही हिस्सा है, जहां पवार परिवार का प्रभाव लंबे समय से कायम है। इस बार अजित पवार भाजपा समर्थित पैनल के साथ मिलकर मैदान में हैं और वे हर हाल में बंपर जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। भीड़ के सामने दिए गए बयान में उनका स्वर मानो यही कह रहा था—"अगर हम सत्ता में हैं, तो विकास भी हमारे जरिए ही मिलेगा।" लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या लोकतंत्र में विकास किसी एक दल की जीत से बंधा होना चाहिए?

इन सबके बीच चुनाव आयोग पर भी दबाव बढ़ गया है कि वह इस घटना का संज्ञान ले और यह तय करे कि नेताओं के ऐसे बयानों पर उसकी नीति क्या है। विपक्ष की मांग है कि डिप्टी सीएम के इस बयान को सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि मतदाताओं को प्रत्यक्ष धमकी की श्रेणी में रखा जाए। अभी तक अजित पवार ने अपने बयान पर कोई सफाई नहीं दी है, लेकिन मालेगांव में यह मामला चुनाव की हवा को गर्म कर चुका है।

नई पूंजी दौड़ में IDBI बैंक बना केंद्र, निजीकरण की हलचल के बीच कोटक महिंद्रा बैंक की एंट्री से बढ़ी हलचल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। IDBI बैंक का निजीकरण लंबे समय से चर्चा में था, लेकिन अब यह मामला एक निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ता दिख रहा है। नई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वैश्विक निवेश दिग्गज ओकट्री कैपिटल और फेयरफैक्स के साथ कोटक महिंद्रा बैंक का नाम भी संभावित खरीदारों की सूची में शामिल हो गया है। यह पहली बार है जब किसी बड़े निजी भारतीय बैंक का नाम इस सौदे से सीधे तौर पर जुड़ रहा है, जिसने बाजार में नई जिज्ञासा और चिंता दोनों पैदा कर दी हैं।

कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी तक अपने इरादों का न तो समर्थन किया है और न ही खंडन, लेकिन वित्तीय जगत के गलियारों में चल रही चर्चाएँ इशारा कर रही हैं कि यह सौदा आकार ले सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि कोटक आगे बढ़ता है, तो उसके लिए यह सौदा केवल विस्तार का अवसर ही नहीं बल्कि बैंकिंग व्यवस्था में एक बड़े पुनर्गठन का संकेत भी देगा।

IDBI बैंक का बाजार पूंजीकरण लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के आसपास है। इस हिसाब से 60% हिस्सेदारी खरीदने के लिए इच्छुक निवेशक को मोटा निवेश करना होगा। यह सौदा केवल नकद में संभव नहीं होगा, इसलिए चर्चा है कि कोटक महिंद्रा बैंक इक्विटी और कैश—दोनों को मिलाकर एक संयुक्त मॉडल अपना सकता है, जिससे सौदा आसानी से वित्तपोषित हो सके। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह वित्त वर्ष 2026 से पहले बैंक के निजीकरण को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संकेत भी मिल चुके हैं कि बोली प्रक्रिया अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में शुरू की जा सकती है। निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने लगभग सारी औपचारिक तैयारियाँ पूरी कर ली हैं।

IDBI बैंक पर वर्तमान में केंद्र सरकार के पास 45.48% और एलआईसी के पास 49.24% हिस्सेदारी है। हालांकि, बिक्री के लिए केवल 61% हिस्सेदारी को सूचीबद्ध किया गया है।

एलआईसी, जिसने 2019 में बैंक को संकट से उबारने के लिए नियंत्रण संभाला था, अब प्रवर्तक की श्रेणी से हटकर केवल एक वित्तीय निवेशक की भूमिका में आ चुका है। इस पुनर्वर्गीकरण से एलआईसी का बोर्ड में दखल खत्म हो गया है और बैंक के कामकाज पर उसका प्रभाव सीमित हो गया है।

निजीकरण की खबरों ने निवेशकों को उत्साहित भी किया और चिंतित भी। शुक्रवार को IDBI बैंक का शेयर 2.53% गिरकर 100.25 रुपये पर बंद हुआ, जो यह दर्शाता है कि बाजार फिलहाल अटकलों के दौर से गुजर रहा है। यदि कोटक महिंद्रा बैंक या कोई बड़ा निवेशक अंतिम दौड़ में पहुँचता है, तो यह भारतीय बैंकिंग उद्योग में पिछले एक दशक के सबसे बड़े निजीकरण सौदों में से एक होगा।

बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि IDBI बैंक के निजीकरण से भारतीय वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा तीव्र होगी। खासकर तब जब खेल में कोटक जैसा स्थापित और तेजी से उभरता बैंक शामिल हो। सरकार, आरबीआई और वित्तीय निवेशकों की नज़र अब बोली आमंत्रण पर टिकी है, जिससे अगले कुछ महीनों में यह तय हो जाएगा कि IDBI बैंक का भविष्य किस दिशा में जाएगा।

अमेरिकी अदालत का कड़ा प्रहार: बायजूस के संस्थापक बायजू रवींद्रन पर 1 अरब डॉलर से अधिक भुगतान का आदेश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत के स्टार्टअप इतिहास की सबसे चमकदार कहानियों में गिने जाने वाले Byju's और उसके संस्थापक बायजू रवींद्रन पर अब कानूनी संकट का सबसे बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। अमेरिका की डेलावेयर स्थित दिवालियापन अदालत ने कड़े शब्दों में कहा है कि रवींद्रन ने अदालत के आदेशों की अवहेलना की, सुनवाई से दूरी बनाकर रखी और उन वित्तीय दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया जिनकी जानकारी मांगी गई थी। इसके चलते अदालत ने उनके खिलाफ डिफॉल्ट जजमेंट पास करते हुए 1 अरब डॉलर से भी अधिक की राशि चुकाने का निर्देश दिया है। यह फैसला 2021 में लिए गए 1.2 अरब डॉलर के टर्म लोन की जांच के दौरान सहयोग न करने के कारण आया है, जिससे Byju's की प्रतिष्ठा और भविष्य पर गंभीर असर पड़ना तय माना जा रहा है।

अदालत की टिप्पणी साफ है—रवींद्रन ने न केवल अपने वित्तीय रिकॉर्ड समय पर नहीं सौंपे, बल्कि कई मौकों पर अदालत के समक्ष उपस्थित होने से भी बचते रहे। इसके चलते इस वर्ष उन्हें पहले अवमानना का दोषी ठहराया गया था और उन पर 10,000 डॉलर प्रतिदिन का भारी जुर्माना लगाया गया। यह राशि अब लाखों डॉलर तक पहुँच चुकी है। न्यायाधीश ब्रेंडन शैनन ने आदेश देते हुए कहा कि अब रवींद्रन को अल्फा फंड्स तथा उससे जुड़े सभी सौदों की पूरी, सटीक और पारदर्शी वित्तीय जानकारी कोर्ट में जमा करनी होगी ताकि लेंडर्स के आरोपों की जांच आगे बढ़ सके। कर्जदाताओं ने रवींद्रन, उनकी पत्नी और उनके एक सहयोगी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने एक सुनियोजित साज़िश के तहत लगभग 533 मिलियन डॉलर की राशि को गलत तरीके से अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की। हालांकि रवींद्रन और उनकी टीम ने इस पूरे मामले को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज किया, लेकिन अदालत के सामने उनकी चुप्पी और दस्तावेजों की कमी ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी।

कभी भारत का सबसे बड़ा एडटेक ब्रांड रह चुका Byju's आज कठिन दौर से गुजर रहा है। एक समय 22 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर पहुंची इस कंपनी ने वैश्विक स्तर पर अपने विस्तार के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया था। कतर में FIFA विश्व कप स्पॉन्सरशिप, भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी पर Byju's का लोगो, अमेरिका और यूरोप में कई एडटेक कंपनियों का अधिग्रहण—इन सबने कंपनी को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई, लेकिन तेज़ी से बढ़ते खर्च, घाटे में बढ़ोतरी, कर्जदाताओं के साथ विवाद, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की खामियाँ और बाजार में गिरती साख ने कंपनी को मुश्किल में डाल दिया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी अदालत का यह फैसला न केवल रवींद्रन के लिए बल्कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ा संकेत है। यह मामला उन स्टार्टअप्स के लिए चेतावनी है जिन्होंने तेज़गति से विस्तार और भारी निवेश पर आधारित रणनीति अपनाई थी, लेकिन वित्तीय पारदर्शिता, समय पर फाइलिंग और जवाबदेही को उतनी गंभीरता से नहीं लिया।

Byju's के लिए आगे की राह कठिन होने वाली है। अब अदालत द्वारा मांगे गए वित्तीय रिकॉर्ड जमा करने, जुर्माना चुकाने और कर्जदाताओं के आरोपों का सामना करने के बीच कंपनी को अपने अस्तित्व की लड़ाई जारी रखनी होगी। निवेशकों का भरोसा टूट रहा है और ग्राहकों की नाराज़गी भी बढ़ रही है।

भारतीय एडटेक सेक्टर को भी इस घटना ने झकझोर दिया है, क्योंकि यह पहला मौका है जब किसी भारतीय संस्थापक को विदेशी अदालत द्वारा इतने बड़े वित्तीय दंड का सामना करना पड़ा है।

अमेरिकी अदालत की कठोर टिप्पणी और भारी जुर्माने का यह आदेश साफ कर देता है कि वैश्विक मंच पर नियमों की अनदेखी और अदालत की अवमानना ऐसी भूलें हैं जिनकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है।